ISSN (Print): 3048-6459

IEARJ

INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLIED RESEARCH JOURNAL

Peer Reviewed International Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Volume : 02 | Issue : 07 | July 2025

iearjc.com

Editor,
INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLIED RESEARCH JOURNAL
Indore - 452020. (Madhya Pradesh, India)
Email Id : info@iearjc.com | Website : iearjc.com | Contact No : +91-7974455742

INTERNATIONAL EDUCATIONAL APPLIED RESEARCH JOURNAL
PEER REVIEWED JOURNAL- EQUIVENT TO UGC JOURNAL

ISSN (Print) 3048-6459 & ISSN (Online) 2456-6713

Volume: 02 & Issue: 07

Month: July-2025

Starting Year of Publication: 2024

Frequency Year of Publication: Monthly

Format: Print Mode

Subject: Multidisciplinary

Language: Multiple Language (English & Hindi)

Published By:

International Educational applied Research Journal

Publisher's Address:

56, Sarthak vihar, Mirjapur, Indore-452020, and Madhya Pradesh

Printer:

International Educational applied Research Journal

Copyright:

International Educational applied Research Journal

Editor Board

Editor in Chief

Name	Designation	Affiliation/Address
Dr. Deependra Sharma	Associate Professor	GMERS Medical Collage, Valsad, Gujarat Email Id: info@iearjc.com Cont. No.8980038054

Emeritus Editor

Name	Designation	Affiliation/Address
Dr. Prasanna Purohit	Associate Professor	Department of Microbiology and Botany, Dr. A. P. J Abdul Kalam University Indore M.P Email Id: purohit_prasann@yahoo.com Conct. No.: 735401777

Executive Editor

Name	Designation	Affiliation/Address
Dr. Rina Sharma	Prof & HOD Obs and Gynae	Principal Autonomous state medical college, Amethi, U.P E-mail ID: principalgmcamethi@gmail.com
Dr. Manish Mishra	Associate Professor Biochemistry	Rajarshi Dasharath Autonomous State Medical College, Ayodhya, U.P Conct Number:9452005795,8887858880 Email Id: drmanishreena@gmail.com
Dr. Pawan Goyal	Professor and Head Department of Physiology	Kiran Medical College, Surat, Gujarat E-mail Id: pawan.goyal@kiranmedicalcpllege.com

Asst. Editor

Name	Designation	Affiliation/Address
Dr. Ashal Shah	Lecture	Department of Pharmacology, GMERS Medical college halarroad, nanakwada, valsad-396001 Gujarat E-Mail Id: aashal_167@yahoo.co.in Conct No. 7990955609
Dr. Boski Gupta	Lecturer	Department of Dentistry GMERS Medical college, Gandhinagar, Gujarat

Technical Editor (Language and Reference)

Name	Designation	Affiliation/Address
Mitasha Purohit	Technical Editor	Editor Office Indore M.P India
Vedant Sharma	Technical Editor	Editor Office Indore M.P India

National Editorial Board		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Amit Jain	Head R&D	Veer pharmachemJhagadia Bharuch Gujarat E-mail ID: amit.jain@veerpharmachem.com Conct. No. 7020692540
Dr. Jimi B. Hadvaid	Physician	Department of Homoeopathic (Enlisted) Physician, Ahmedabad-380001
Dr. Deepak Saxena	Director	IIPHG Ga dhinager Gujarat Email ID: director@iiphg.org & ddeepak72@iphg.org

International Editorial Board		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Dr. Sukhprit Purewal	Medical Laboratory Program Instructor	1300 Central Parkway West, Suite 400, Mississauge, ON L5C 4G8 CDAANA E-mail ID: s.purewal@oxfordeduca
Satya Dev Sharma	Director of Engineering	Address: Director of Engineering IVANTI Utah, USA. E-mail ID: Satyadev.sharma@ivanti.com
Dr. Prabhjot Singh	Advisor	Advisor, Health Surveillance, Disease Prevention and Control Pan American Health Organization/World Health Organization Office for Barbados, Eastern Caribbean Countries and the French Departments E-mail ID singhpra@paho.org

Publisher		
Name	**Designation**	**Affiliation/Address**
Mitasha Purohit	Technical Editor	Editor Office Indore M.P India
Editor Office Address		
56, SarthakVihar, Mirjapur, Indore M.P. PIN-452020		
Conct. No.		
+91-7974455742, 91-8980038054 | E-mail Id: info@iearjc.com		

INDEX

S. No.	PAPER TITLE AND AUTHOR NAME	PAGE No.
1.	व्यग्य का सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व	1
2.	PORTRAYAL OF GENDER ROLES IN FAMOUS SHAKESPEAREAN TRAGEDIES	8
3.	रियासतों का एकीकरण और मध्य प्रदेश का गठन: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	13
4.	मध्य प्रदेश में मानव बस्ती के सबसे शुरुआती प्रमाण: प्रागैतिहासिक काल का एक अवलोकन	19
5.	1857 का स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका	25
6.	The Role of Language Proficiency in Enhancing Entrepreneurial Opportunities and Economic Empowerment : A Business Management perspective	31
7.	जंक फूड एक अभिशाप : स्वास्थ्य के संदर्भ में	40
8.	GREEN BANKING AWARENESS AND CUSTOMER ADOPTION PATTERNS : INSIGHTS FROM RAJASTHAN'S BANKING SECTOR	46
9.	मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का ऐतिहासिक उपदेयता	60
10.	मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का राजनैतिक एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता	65

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

व्यग्य का सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व

चन्द्रप्रभा तिवारी

शोध छात्रा,विषय – हिंदी, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16329675

IMPACT FACTOR

5.924

शोध सार

समाज के बिना साहित्य की परिकल्पना संभव नहीं है। लेकिन समाज बडा ऊबड़-खाबड़ और विषम होता है। साहित्य समाज के इस ऊबड़-खाबड़ स्वरूप को सामने लाता है। समाज में इतनी विषमता व्याप्त होती है कि उसके बारे में केवल अच्छा-अच्छा कहने से काम नहीं चलता । साहित्य समाज के भद्दे चेहरे का वर्णन करके सामने लाता है। समाज में व्याप्त अत्याचार, हिंसा, विषमता आदि को सामने लाकर समाज को जागरूक बनाने का सबसे सशक्त साधन व्यंग्य है। जब- जब समाज की स्थिति विसंगत होती है, तब-तब उसकी ओर लोगों का ध्यान ले जाने के लिए व्यंग्य की आवश्यकता होती है। इस प्रकार व्यंग्य समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के मूल में होता है यथास्थिति का बदलाव; समाज में बदलाव लाना ।

साहित्य की प्रत्येक विधा का मूल उद्देश्य परिवर्तन की क्रांतिकारी चेतना का संचार करना और समाज को सीधे रास्ते पर लाना है। अतः कहानी हो या कविता, नाटक हो या कोई भी व्यंग्य के तत्त्व से अछूता नहीं रह पाता है।

मुख्य विन्दु : परिकल्पना, समाज, विषमता, क्रांतिकारी, व्यंग्य

आज तो चलचित्रों में भी उपन्यास समाज की विसंगतियों एवं विषमताओं माध्यम से को प्रस्तुत करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यंग्य समकालीन समाज की माँग है । व्यंग्य के हँसते-हँसते बहुत कुछ कह दिया जाता है; और लोग हँसते हुए कही हुई बात का बुरा न मानकर उस पर गंभीरता से विचार भी करने लगते।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

व्यंग्य शब्द अंग्रेजी सटायर के अर्थ में हिन्दी में चलता है। पाश्चात्य साहित्य में रोम में 65 ई. पू. सटायर शब्द का प्रयोग लगातार नाटक के लिए होता था। वहीं लैटिन में सैतुरा विकसित हुआ, जिसका अर्थ गड़बड़झाला होता है। अर्थात् सैतुरा शब्द परनिंदा के अर्थ में प्रयुक्त होता था। वही बाद में अंग्रेजी में सटायर बन गया। अंग्रेजी सटायर के लिए हिन्दी में व्यंग्य, व्यंग, उपहास, विकृति, विरूप, व्यंजना शक्ति द्वारा ध्वनित व्यंग्यार्थ आदि होता है ।

संस्कृत के' शब्दकल्पद्रुम' व्यंग्य को समझाते हुए कहा गया है अंगानि यस्मात्। अतः उपर्युक्त बातों से साफ हो जाता है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त विषमता एवं विकलांगता जब बढ़ती है, तब व्यंग्य समाज का रक्षक बनकर कार्य करता है। इस प्रकार व्यंग्य और व्यंग्यकार का काम समाज के विकृत एवं गलित अंगों के प्रति समाज को सचेत करना है। पं. कालिकाप्रसाद ने बृहद् हिन्दी कोश में व्यंग और व्यंग्य की व्याख्या अलग-अलग अर्थों में की है। उन्होंने व्यंग शब्द का अर्थ शरीरहीन, विकलांग एवं अव्यवस्थित दिया है; और व्यंग्य को समझाते हुए वे लिखते हैं कि व्यंजना वृत्ति द्वारा बोधित, संकेतित अर्थ यानी संकेतार्थ, गूढ़ार्थ तथा चिढ़ाने, नीचा दिखाने आदि के उद्देश्य से कहे गए विपरीतार्थबोधक ताना शब्द कहा गया है।

माना कि व्यंग और व्यंग्य शब्दों को लेकर हिन्दी में मतभेद रहा है; किंतु दोनों शब्दों की अर्थाभिव्यक्ति एक समान है। कहने का मतलब यह है कि व्यंग्य का व्यंजना वृत्ति द्वारा बोधित अर्थ यानी संकेतार्थ, ताना आदि के जन्म के पीछे समाज एवं मनुष्य जीवन का वह परिवेश है, जो विकृति, बौनापन, विद्रूपता एवं विषमता से भरा हुआ है। परिणामस्वरूप व्यंग्यकार अपने व्यंग्य के माध्यम से समाज के विकृत एवं गलित अंगों के प्रति हमारा ध्यान खींचता है। Encyclopaedia Ammerica में लिखा है 'A literary work in prose or verse, often humorous] in whith wickedness or folly consured and made ridiculous.' 'सटायर गद्य या पद्य के रूप में वह साहित्यिक कृति है, जिसमें दुष्टता और मूर्खता की आलोचना करते हुए उसे उपहासास्पद बना दिया जाता है। Encyclopaedia Britanica: Satire in its literary aspect] may be difined as the eÛpression] in adequate terms, of the sense of amusement or disgust eÛited by ridiculous or unseemly, provided that humour is distinctly recognizable element] and the utterance is invested with literary form- Wthout humour it is invictive]without literary form it is more clowrish jeering.' 'व्यंग्य की साहित्यिक तथा ग्राह्य परिभाषा हास्यास्पद अथवा निंदक तथ्यों की मनोरंजक अथवा

घृणोत्पादक अभिव्यक्ति के रूप में दी जा सकती है। बशर्ते कि हास्य तत्त्व साहित्यिक रूप में स्पष्टतः परलिक्षित हो । हास्य के अभाव में व्यंग्य केवल लांछन तथा साहित्यिकता के अभाव में विदूषकी परिहास मात्र है । (1)

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुचित व्यवस्था तंत्र अनुचित मानव व्यक्तित्व तथा अनुचित परिस्थितियाँ व्यंग्य के जन्म का कारण हैं। केवल हास्य या केवल निंदा करना व्यंग्य का कार्य नहीं है । अतः व्यंग्य की सार्थकता हास्य के सहयोग से निंदा करके समाज को सचेत करने में है। पाश्चात्य साहित्य जगत के अनेक समीक्षकों एवं रचनाकारों ने व्यंग्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो इस प्रकार हैं।

–जॉन एम. बुलिट ने व्यंग्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है

मानव अथवा उसके आचारों की मूर्खताओं अथवा सदोषता पर किया गया साहित्यिक प्रहार, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सामान्य हो या विशिष्ट, सत्य हो या असत्य, क्रूर हो या हास्यास्पद, गद्य हो या पद्यमय सब व्यंग्य शब्द के अंतर्गत है। (2)

सटायर कटु आलोचना का साधन है। उससे कड़वी सच्चाई बयान होती है। वे सटायर को कटु आलोचना और हास्य से युक्त मानते हैं । इसीलिए वे कहते हैं कि 'हास्यास्पद का इतना अधिक मजाक उड़ाया जाता है कि उसमें दया एवं सहानुभूति समाप्त हो जाए, तब वह हास्य व्यंग्य की कोटि में आ जाता है। वे व्यंग्य का मूल धर्म उपहास मानते हैं ।

स्विफ्ट के मतानुसार- 'व्यंग्य एक प्रकार का शीशा है, जिसमें देखने वाले को अपने मुख के अतिरिक्त प्रत्येक का मुख दिखाई देता है। यही कारण है कि विश्व में व्यंग्य का स्वागत किया जाता है। कम लोग इससे अपने को पीड़ित अनुभव करते हैं। (3)

इस तरह स्विफ्ट ने व्यंग्य की सामाजिक सार्वजनिक व्यापकता पर जोर दिया है।

प्रो. राधेश्याम शर्मा इस बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि व्यंग्य में हँसी आएगी। यदि व्यंग्य चेतना को छेड़ देता है, दुख को सामने ला खड़ा करता है, सोचने को बाध्य करता है, व्यवस्था की सड़ांध पर सोचने को बाध्य करता है और परिवर्तन की ओर प्रेरित करता

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

है, तो व्यंग्य अपने में सफल है। जितना व्यापक परिवेश होगा, जितना तिलमिला देने वाली विसंगति होगी, व्यंग्य उतना ही सार्थक होगा । पाश्चात्य रचनाकारों एवं आलोचकों के व्यंग्य संबंधी विचारों के आधार पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती हैं

- व्यंग्य का जन्म अव्यवस्था और विकृतियों से होता है ।
- व्यंग्य का उद्देश्य जीवन की विषमताओं की आलोचना करना तथा विसंगतियों, मिथ्याचारों और विकृतियों के प्रति समाज को सचेत करना है।
- व्यंग्य का कार्य जीवन की समस्त विकृतियों एवं निंदनीय तथा नकारात्मक व्यवस्था का साहित्यिक ढंग से कलात्मक विरोध करना और उसे नग्न करना तथा उसे नष्ट करके समाज के नवनिर्माण की प्रेरणा देना है।

अतः हम कह सकते हैं कि पुरानी, सड़ी-गली तथा विकृतियों से ग्रस्त व्यवस्था से बचने के लिए मनुष्य की स्वयं की शक्ति ही उसे संतोषजनक जगत की खोज करने की प्रेरणा देती है। व्यंग्य यहाँ साधन बनकर आता है। साहित्य के माध्यम से व्यंग्य एक स्वस्थ जगत का निर्माण करने का प्रयत्न करता है।

मैथ्यू हागर्थ के अनुसार -

व्यंग्य चेतावनी देता है कि मनुष्य वह खतरनाक जानवर है, जिसमें मूर्खतापूर्ण कार्य करने की असीम क्षमता है और यदि व्यंग्य द्वारा इस सत्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति कर दी जाती है, तो वह पर्याप्त है। मनुष्य के गौरव का वर्णन करना कवियों का कार्य है। इस प्रकार साहित्य का एक अभिन्न अंग व्यंग्य बन जाता है।

- भारतीय समीक्षकों और रचनाकारों की दृष्टि में व्यंग्य

हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार –व्यंग्य वह है, जहाँ कहने वाला अधरोष्ठों में हँस रहा हो, और सुनने वाला तिलमिला उठा हो ।

इंद्रनाथ के अनुसार परिवेश के लिए असंतोष व्यंग्य का रूप धारण करता है। - इसे खरी-खरी सुनाना भी कहा गया है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

डॉ. शेरजंग गर्ग मानते हैं –'व्यंग्य एक ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति या रचना है, जिसमें व्यक्ति तथा समाज की कमजोरियों, दुर्बलताओं तथा कथनी और करनी के अंतरों की समीक्षा अथवा निंदा भाषा को टेढ़ी भंगिमा देकर अथवा कभी-कभी पूर्णतः सपाट शब्दों में प्रहार करते हुए की जाती है। वह पूर्णतः अगंभीर होते हुए भी गंभीर हो सकती है, निर्दय लगते हुए दयालु हो सकती है, प्रहारात्मक होते हुए तटस्थ हो सकती है, अतिशयोक्ति एवं अतिरंजना का आभास देने के बावजूद पूर्णतः सत्य हो सकती है। (4)

हरिशंकर परसाई के मतानुसार व्यंग्य जीवन से साक्षात्कार करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों, मिथ्याचारों और पाखंडों का पर्दाफाश करता है ।

कन्हैयालाल नंदन मानते हैं व्यंग्य आक्रोश का उबलता हुआ तूफान नहीं है, पीड़ा और आक्रोश का संयमपूर्ण सृजन है –हाँ, संयमपूर्ण सृजन ! जहाँ आदमी आक्रोश से पागल नहीं हो जाता, वह अपने आक्रोश को पिघले हुए ताँबे के रूप में तपाकर रचनात्मक साँचे में ढालता है, ताकि विकृति चौराहे पर नंगी खड़ी की जा सके ।

कन्हैयालाल नंदन मानते हैं व्यंग्य आक्रोश का उबलता हुआ तूफान नहीं है, पीड़ा और आक्रोश का संयमपूर्ण सृजन है –हाँ, संयमपूर्ण सृजन ! जहाँ आदमी आक्रोश से पागल नहीं हो जाता, वह अपने आक्रोश को पिघले हुए ताँबे के रूप में तपाकर रचनात्मक साँचे में ढालता है, ताकि विकृति चौराहे पर नंगी खड़ी की जा सके ।

बालेन्दुशेखर तिवारी का मानना है व्यंग्य एक विशिष्ट समाजधर्मी प्रेक्षण – विधि अथवा एक विशिष्ट मानसिक भंगिमा है, जिसका उद्भव अंतविरोधों के कारण होता है और जिसमें व्यक्ति अथवा व्यवस्था के दौर्बल्य की आक्षेपात्मक अभिव्यक्ति द्वारा परिवर्तन का अभीष्ट पूर्ण होता है। " (5)

शरद जोशी के मतानुसार – व्यंग्य सेन्स ऑफ ह्यूमर है, जो अन्याय अत्याचार और निराशा के विरुद्ध होने से व्यंग्य में अभिव्यक्त होता है ।

बेढब बनारसी मानते हैं जब किसी व्यक्ति या समाज की बुराइयों या न्यूनता –को सीधे शब्दों में न कहकर उल्टे या टेढ़े शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब व्यंग्य की सृष्टि होती है। व्यंग्य एक प्रकार की आलोचना है; किंतु जब व्यंग्य में क्रोध आ जाता है, तो हास्य की मात्रा कम हो जाती है

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- **हिंदी साहित्य में व्यंग्य का उद्भव और विकास**

व्यंग्य युगीन विसंगतियों की वैविध्यपूर्ण तीखी अभिव्यक्ति है। युग की विसंगतियाँ हमारे चारों ओर के यथार्थ जगत से, वैदग्ध्य इन विसंगतियों को वहन करने वाले शैली सौष्ठव से तथा तीखेपन, विसंगत एवं वैदग्ध्य की चेतना पर पड़ने वाले मिले-जुले प्रभाव से संबंधित है।

इस प्रकार भारतीय तथा पाश्चत्य विद्वानों के व्यंग्य संबंधी विचारों तथा परिभाषाओं का गहन अध्ययन करने से एक बात स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि व्यंग्य की परिभाषा पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है । व्यंग्य की जो भी परिभाषाएँ देखने को मिलती हैं, वे सब व्यंग्य के बहुरूपी स्वरूप से प्रभावित हैं। इसीलिए व्यंग्य के बारें में कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यंग्य हास्य का विशेष भेद है। साथ ही उन्होंने व्यंग्य में हास्य को अनिवार्य तत्त्व के रूप में भी स्वीकार किया है। 'उन विद्वानों में काका हाथरसी, आ. हजारीप्रसाद द्विवेदी, बेढब बनारसी और जार्ज मेरेडिथ का नाम उल्लेखनीय है । बर्नार्ड शॉ भी इसी श्रेणी के विद्वान् हैं। उन्होंने सहानुभूतिहीन हास्य को व्यंग्य के रूप में स्वीकार किया है । (6)

दूसरी ओर डॉ. शेरजंग गर्ग, श्री बालेन्दुशेखर तिवारी, श्री शंकर पुणतांबेकर, श्री हरिशंकर परसाई, श्री कन्हैयालाल नंदन, श्री इंद्रनाथ मदान जैसे विद्वानों ने व्यंग्य के अंतर्गत हास्य को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया है। उन्होंने व्यंग्य को क्रांति का अस्त्र माना है। व्यंग्य केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। बल्कि उसका उद्देश्य समाज और व्यक्ति की आलोचना करके उनकी निंदा करके उनमें सुधार लाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है।

व्यंग्य सामज के पाखंड, भ्रष्टाचार, असमानता, शोषण, अन्याय, विकृति तथा जन-विरोधी तथ्यों की गोद में पलता है; और यही उसके प्रेरणा-स्रोत हैं । व्यंग्य समाज की विसंगतियों और विकृतियों से उत्पन्न परिस्थिति की आलोचना करके उसके आदर्श पक्ष की स्थापना करता है। अथात् बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय के आदर्श को स्थापित करना ही उसका उद्देश्य है । साहित्य रचना के रूप में शिष्टता और शालीनता व्यंग्य के आवश्यक गुण हैं। व्यंग्य में

वाग्जाल एवं मनोरंजन नहीं होता; बल्कि वह तिलमिलाहटों तथा कसक से भरपूर होता है। इस तरह व्यंग्य में हास्य अनिवार्य तत्त्व नहीं है ।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

इस प्रकार व्यंग्य का लक्ष्य मानवीय दुर्बलताओं पर कटाक्ष करके उन्हें उभारना और सुधारना होता है। जहाँ कहीं विषमता, विसंवादिता और विकृतियाँ नजर आती हैं, वहाँ पर व्यंग्यकार आहत हो उठता है और कलम लेकर उनसे लड़ने निकल पड़ता है । आज साहित्य में या अन्य क्षेत्रों में भी व्यंग्य केंद्र स्थान में है। आज के सृजन के लिए वह एक अनिवार्य शर्त बन गया है; क्योंकि आज समाज में व्यंग्य अंतर्यामी देवता की भाँति सर्वत्र विद्यमान है। यही वजह है कि व्यंग्य ने दैनिक पत्रों से लेकर रेडियो तक तथा थिएटर से लेकर टी.वी. तक सभी जगह अपना डेरा डाले हुए है। हर विधा में कहीं न कहीं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में व्यंग्य विद्यमान रहता है ।

संदर्भ सूची

1. प्रसाद कमला 'आँखन देखी' : वाणी प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण, 1981 पृ.86
2. जैन कांतिकुमार, 'प्रथम तुम्हारा परसाई : वाणी प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 1988 पृ. 108
3. परसाई हरिशंकर : व्यकितत्व एवं कृतित्वः डॉ. मनोहर देवलिया, साहित्यवाणी, इलाहाबाद, 1986 पृ. 84
4. देवलिया मनोहर : हरिशंकर परसाई की दुनियाः साहित्यवाणी प्रकाशन,इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1985 पृ. 12
5. व्यास मदालशा : हिन्दी व्यंग्य साहित्य और हरिशंकर परसाई : विश्वविद्यालय प्रकाशन, प्रथम संस्करण, 1999 पृ. 58
6. जैन संध्या : परसाई का इतिहास बोध : विकास प्रकाशन, कानपुर, प्रथम संस्करण, 2003 पृ. 172

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

PORTRAYAL OF GENDER ROLES IN FAMOUS SHAKESPEAREAN TRAGEDIES

Dr. Anamika Lata

Assistant Professor, Department of English

S.G.N KHALSA P.G College, Hanumangarh,RAJ.

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16617212

IMPACT FACTOR

5.924

Abstract

Shakespeare's tragedies, which are timeless works of English literature, present complex and even paradoxical depictions of gender roles. Despite appearing to be limited by the patriarchal standards of the Elizabethan period, Shakespeare regularly questions, subverts, and blurs conventional expectations for both men and women. This essay will examine the complex ways in which gender is portrayed in well-known Shakespearean tragedies like *King Lear, Macbeth, Othello, and Hamlet*. It will examine how, in spite of their limited agency within the social framework, female characters frequently hold tremendous power and exhibit complexity that is difficult to pin down. On the other hand, it will look at the ways in which masculine characters struggle with the expectations of masculinity in society, producing both heroic and catastrophic result. This paper explores these theatrical representations to make the claim that, although representing his era, Shakespeare also went beyond it to create characters whose struggles with gender identity and social expectations communicate to viewers today. According to the research, women are frequently depicted in Shakespeare's plays as the objects of masculine jealousy and ambition. By questioning gender norms and preconceptions, Shakespeare's female characters offer a more complex and powerful perspective on women. In Shakespeare's tragedies, women play important parts that subvert gender norms and beliefs. The study emphasizes how crucial it is to take into account Shakespeare's historical setting when examining how he portrayed women, as well as how relevant his female characters are to current society.

Keywords - Shakespeare, Tragedies, Gender Roles, Beliefs, Female, Masculine.

Introduction -

Written in the late 16th and early 17th centuries, William Shakespeare's tragedies continue to be a mandatory read for anyone interested in human nature, power dynamics, and social systems. Among the many deep issues that are present in these masterpieces, the representation of gender roles is one that is especially intricate and nuanced. During the Elizabethan period, women were mostly restricted to the home and defined by their connections with males in a strict, patriarchal society. However, Shakespeare regularly broke with these social conventions within the Globe Theatre's dramatic framework, offering both male and female characters who both fit and remarkably defy traditional gender stereotypes. *Hamlet, Othello, Macbeth, and King Lear* are just a few of the well-known Shakespearean tragedies whose complex portrayals of gender roles will be examined in this paper.

I. Female Agency and Subversion within Patriarchal Structures:

Shakespeare's female characters frequently defy the norms of their era by being nuanced and multidimensional. Shakespeare's female characters are among the most captivating and unforgettable in all of writing, according to some critics, while others claim that his depiction of women is constrained by the cultural conventions of his time. Shakespeare's ideas on gender and the place of women in society can be better understood by analyzing these characters within the framework of their individual plays. Shakespeare's depiction of women illustrates Elizabethan England's shifting views on gender roles. Shakespeare questions conventional ideas of femininity and portrays women as capable, intellectual, and independent people. Despite the restrictive social environment, Shakespeare's tragic female characters often exhibit remarkable agency, intelligence, and even a subversive power that challenges the patriarchal order. Their influence, though sometimes indirect or tragic in its consequences, is undeniable.

Hamlet's Ophelia and Gertrude represent distinct aspects of female agency and vulnerability in a corrupt court. As queen, Gertrude, who at first seems weak-willed and complicit in her new marriage, has considerable political influence. Although Hamlet rejects her quick and unethical remarriage, it is also a deliberate political act in a precarious court (Bloom 399). Her mental condition and moral agency, however, are frequently contested; is she an intentional participant in the tragedy or a victim of her circumstances? Ophelia, on the other hand, is continuously influenced by the men in her life, including Hamlet, her brother Laertes, and her father Polonius. Her fall into madness which is frequently credited to her lack of self-control and the death of her male guardians, can also be viewed as a kind of rebellion—a liberation from the limitations of reason and social norms, even if it is ultimately harmful (Showalter 297). The male-dominated environment that has drenched her in madness is starkly highlighted in her songs and broken speech.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Othello's Desdemona and Emilia provide a striking example of feminine loyalty and honesty, as well as a tragic depiction of female virtue and their downfall. Desdemona conforms to the idealized feminine norms of the time by embodying purity, fidelity, and unwavering love. Her firm commitment to Othello, despite his baseless envy, emphasizes her inherent kindness. Even though it is terrible, her timid acceptance of her fate also highlights how little a woman can do in her society to protect herself from male wrath and patriarchal suspicion. In contrast, Iago's wife Emilia first plays the subservient role of a wife but later becomes an important voice of opposition and truth. Her fierce condemnation of Iago's villainy, even at the cost of her own life, is a potent act of defiance against the oppression and deceit of men. Her final remarks reveal the lies and demonstrate her devotion to Desdemona, demonstrating a type of female solidarity.

In Macbeth, Lady Macbeth Perhaps the most notable example of a female character that aggressively challenges gender norms and propels the tragic drama is Lady Macbeth. She is arguably more cunning and ambitious than Macbeth himself; she is known for requesting that spirits "unsex" her in order to gain power since she wants to remove her feminine flaws (1.5.40-41). She demonstrates a strong, if destructive, agency through her early control over Macbeth, her involvement in the regicide, and her capacity to repress her own guilt. Her subsequent decline into insanity and suicide, however, highlights the negative social and psychological effects of rejecting traditional gender norms and repressing one's humanity (Adelman 95). Her journey highlights the tremendous strain and eventual impossibility of completely avoiding Elizabethan cultural conceptions of gender.

II. Masculinity under Pressure: Honor, Revenge, and Power

The demands of society also affect Shakespeare's male tragic heroes, who frequently struggle with ideas of honor, bravery, and power that ultimately lead to their downfall.

The Crisis of Masculinity in Hamlet Many people read Hamlet's prolonged uncertainty and philosophical reflection as a crisis of traditional masculinity. Hamlet battles the performative elements of kingship and the violent demands of honor as he attempts to exact revenge for the death of his father and regain his proper position (Greenblatt 200). The simple heroic masculinity that is required of a tragic protagonist is challenged by his melancholic attitude, his philosophical questioning of action, and his perceived "effeminacy" by certain critics. His mental conflict is a reflection of his attempt to balance his moral principles with the violent demands of power and revenge.

The Vulnerable Masculinity of Othello- Othello represents a strong, stereotypically masculine character as a strong military leader. The weakness of his self-perception and his dependence on a reputation for honor, however, are shown by his susceptibility to Iago's fraudulent suggestions and his eventual decline into irrational jealously. His stern and military-based masculinity is vulnerable

to the emotional manipulation that ultimately brings him and Desdemona to ruin. His incapacity to restrain his emotions and his vulnerability to the gendered concerns about female chastity that are pervasive in his society are his fatal flaws, not a lack of bravery.

A major issue in Shakespeare's Macbeth is masculinity, which is frequently portrayed as a source of stress and a catalyst for violence. Lady Macbeth and Macbeth both associate masculinity with violence and hostility; this distorted perception fuels Macbeth's ambition and finally brings him to ruin. By challenging her husband's masculinity, Lady Macbeth coerces him into killing, and Macbeth employs the same strategy to incite the killers to murder Banquo. The drama examines how ambition and cultural ideals of masculinity can corrupt even a brave warrior like Macbeth. His attempts to assert his power through increasingly violent acts lead to a dehumanizing path, transforming him from a valiant soldier into a tyrannical murderer.

Rejecting Patriarchal Authority in King Lear King Lear's tragic decision to surrender his throne and his failure to comprehend his daughters' genuine feelings of love and loyalty are the main causes of the tragedy. His strict patriarchal standards are emphasized by his insistence on public displays of affection and his rejection of Cordelia, who declines to engage in his dramatic masculinity. His decline into insanity is closely related to his loss of power and his daughters' violation of the paternal obedient duty that was expected of them, especially Goneril and Regan. However, his pain also compels him to face his previous mistakes and develop empathy, indicating a discomforting shift in his perspective on power and human connection beyond conventionally masculine norms.

Shakespeare's tragedies show how gender roles are inextricably tied to social hierarchy, power relations, and the results of society expectations, in addition to highlighting specific characters. The plays show how strict adherence to gender norms can have negative effects on both men and women. Women's limited options for agency frequently push them to extreme lengths or leave them open to abuse. Men's dedication to strict masculine ideas of honor, retribution, and dominance often leads to violence and personal destruction at the same time. These plays' tragic endings frequently highlight the terrible consequences of either sticking to or destructively defying gender roles that are set within a hierarchical structure.

Conclusion

Shakespeare's well-known tragedies provide incredibly intricate and nuanced depictions of gender roles, while being the product of a strongly patriarchal Elizabethan culture. Shakespeare reflected and deeply questioned the gendered expectations of his era through the tragic outcomes of characters such as Ophelia, Desdemona, Lady Macbeth, Hamlet, Othello, and King Lear. Despite having little social agency, female characters frequently display strong wills, moral clarity, and even a subversive resistance to male authority. At the same time, male characters battle the

expectations of traditional masculinity, which causes them to experience identity crises, act violently, and eventually fall. By magnifying the individual and societal costs of rigid gender norms, Shakespeare's tragedies continue to resonate with contemporary audiences, inviting ongoing reflection on the construction and performance of gender, and the enduring consequences of a society's expectations for its men and women.

Works Cited

1. Adelman, Janet. *Suffocating Mothers: Fantasies of Maternal Origin in Shakespeare's Hamlet, Macbeth, King Lear, and Coriolanus*. Routledge, 1992.
2. Bloom, Harold. *Shakespeare: The Invention of the Human*. Riverhead Books, 1998.
3. Garber, Marjorie. *Shakespeare After All*. Pantheon Books, 2004.
4. Greenblatt, Stephen. *Hamlet in Purgatory*. Princeton University Press, 2001.
5. Kastan, David Scott. *Shakespeare and the Book*. Cambridge University Press, 2001.
6. Maclean, Hugh. *Introduction*. *King Lear*. By William Shakespeare. Signet Classic, 1998. xi-lxxi.
7. Neill, Michael. *Issues of Death: Mortality and Identity in English Renaissance Tragedy*. Clarendon Press, 1997.
8. Shakespeare, William. *Hamlet*. *The Norton Shakespeare*. Edited by Stephen Greenblatt et al., 3rd ed., W. W. Norton & Company, 2016, pp. 1655-1748.
9. *Macbeth*. *The Norton Shakespeare*. Edited by Stephen Greenblatt et al., 3rd ed., W. W. Norton & Company, 2016, pp. 2191-2244.
10. *Othello*. *The Norton Shakespeare*. Edited by Stephen Greenblatt et al., 3rd ed., W. W. Norton & Company, 2016, pp. 1927-2007.
11. Showalter, Elaine. "Representing Ophelia: Women, Madness, and the Responsibilities of Feminist Criticism." *Shakespeare and the Question of Theory*. Edited by Patricia Parker and Geoffrey Hartman.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

रियासतों का एकीकरण और मध्य प्रदेश का गठन: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

Dr. Shalendra Kumar Goutam
NET, P.hd, Jiwaji University,
Gwalior, M.P

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16644800

IMPACT FACTOR
5.924

Abstract

यह शोध-पत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश भारत की रियासतों के एकीकरण की जटिल प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य के गठन के संदर्भ में। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन के नेतृत्व में रियासतों के विलय की राष्ट्रीय नीति को रेखांकित किया गया है, और फिर उन विभिन्न भौगोलिक एवं प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार से विवरण दिया गया है, जिनसे मिलकर 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। यह पेपर एकीकरण की चुनौतियों, राज्य पुनर्गठन आयोग की भूमिका और नवगठित राज्य के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डालता है।

1. प्रस्तावना :

15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ही, एक 'अखंड भारत' का निर्माण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत को दो मुख्य प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया था: ब्रिटिश प्रांत और लगभग 560 से अधिक देसी रियासतें। इन रियासतों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता थी, जो स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त हो गई। इस स्थिति ने रियासतों को स्वतंत्र रहने या भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय करने का विकल्प दिया। ऐसी स्थिति में, भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण अत्यंत आवश्यक हो गया। यह असाधारण कार्य मुख्य रूप से सरदार वल्लभभाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, और उनके सचिव, वी.पी. मेनन द्वारा संभाला गया, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ता

से भारत को खंडित होने से बचाया। मध्य प्रदेश का गठन इसी व्यापक राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम था।

2. रियासतों का एकीकरण: एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

2.1 चुनौती और रणनीति स्वतंत्रता के समय, रियासतें आकार, जनसंख्या, राजनीतिक संरचना और आर्थिक स्थिति में अत्यधिक भिन्न थीं। कुछ विशाल और समृद्ध थीं (जैसे हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर), जबकि कई छोटी और अविकसित थीं। सर्वोच्चता के अंत ने 'बाल्कनीकरण' के खतरे को जन्म दिया, जहाँ प्रत्येक रियासत एक स्वतंत्र इकाई बन सकती थी, जिससे भारत अनगिनत छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता।

सरदार पटेल और वी.पी. मेनन ने इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई:

- विलय पत्र (Instrument of Accession): रियासतों को यह स्वीकार करने के लिए राजी किया गया कि वे रक्षा, विदेश मामलों और संचार के विषयों पर अपनी शक्ति भारत सरकार को हस्तांतरित कर दें। अधिकांश शासकों ने स्वेच्छा से इस पर हस्ताक्षर किए।
- रियासती मंत्रालय (Ministry of States): 5 जुलाई 1947 को स्थापित यह मंत्रालय एकीकरण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बना।
- वित्तीय प्रलोभन (Privy Purses): शासकों को उनके विलय के बदले में पेंशन और कुछ विशेषाधिकारों की पेशकश की गई।
- कठोर कदम (Coercion, where necessary): जहाँ कूटनीति विफल रही, वहाँ दृढ़ कार्रवाई की गई, जैसे जूनागढ़ (जनमत संग्रह), हैदराबाद (पुलिस कार्रवाई - ऑपरेशन पोलो), और कश्मीर (सैन्य हस्तक्षेप)।

2.2 एकीकरण के चरण एकीकरण प्रक्रिया को मोटे तौर पर तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

1. छोटे राज्यों का विलय: कई छोटी रियासतों को पास के बड़े प्रांतों या अन्य रियासतों में एकीकृत किया गया।
2. राज्यों के संघों का निर्माण: मध्य भारत, सौराष्ट्र, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU) जैसे नए राज्यों का निर्माण किया गया, जहाँ कई रियासतें एक साथ मिलकर एक बड़ी प्रशासनिक इकाई बनीं।
3. बड़े राज्यों का भारतीय संघ में विलय: मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन, भोपाल, और इंदौर जैसे बड़े राज्य सीधे भारतीय संघ में शामिल हुए।

3. मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व की स्थिति :

मध्य प्रदेश के गठन से पहले, वर्तमान मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कई अलग-अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित था, जिनमें से प्रमुख थीं:

3.1 मध्य प्रांत और बरार (Central Provinces and Berar): यह ब्रिटिश भारत का एक बड़ा प्रांत था, जिसे स्वतंत्रता के बाद 'भाग अ' (Part A) राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल थे। यह क्षेत्र भाषाई रूप से विविध था, जिसमें हिंदी, मराठी, छत्तीसगढ़ी और गोंडी बोलने वाले लोग शामिल थे।

3.2 मध्य भारत (Madhya Bharat): यह 'भाग ब' (Part B) राज्य था, जिसका गठन 28 मई 1948 को ग्वालियर, इंदौर, मालवा और बुंदेलखंड की 25 रियासतों को मिलाकर किया गया था। इसकी दो राजधानियाँ थीं - ग्वालियर (शीतकालीन) और इंदौर (ग्रीष्मकालीन)। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था।

3.3 विंध्य प्रदेश (Vindhya Pradesh): यह 'भाग स' (Part C) राज्य था, जिसे 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की 35 से अधिक रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी राजधानी रीवा थी। यह क्षेत्र अपनी बीहड़ स्थलाकृति और जनजातीय आबादी के लिए जाना जाता था। 1950 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

3.4 भोपाल राज्य (Bhopal State): यह एक महत्वपूर्ण 'भाग स' (Part C) राज्य था, जिसका शासक (नवाब हमीदुल्ला खान) शुरू में भारतीय संघ में विलय को लेकर अनिच्छुक था। नवाब ने 1 जून 1949 को भोपाल राज्य को भारतीय संघ में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह अपनी संस्कृति और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था।

4. मध्य प्रदेश का गठन: प्रक्रिया और कारक :

4.1 भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता के बाद, भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की तीव्र मांग उठी। विभिन्न भाषाई समूहों ने अपनी-अपनी पहचान और संस्कृति के संरक्षण के लिए अलग राज्यों की वकालत की। इस मांग को संबोधित करने के लिए, भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग (State Reorganisation Commission - SRC) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे और सदस्य के.एम. पणिक्कर तथा हृदयनाथ कुंजरू थे।

4.2 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें और मध्य प्रदेश आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें भाषाई और प्रशासनिक दक्षता दोनों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। मध्य भारत के संदर्भ में, आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं, जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से लागू किया गया:

- मध्य प्रांत और बरार: इसके मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र (जिसमें नागपुर भी शामिल था) को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। शेष हिंदी भाषी क्षेत्रों को नए मध्य प्रदेश राज्य में मिला दिया गया।
- मध्य भारत: संपूर्ण मध्य भारत राज्य को नए मध्य प्रदेश में एकीकृत कर दिया गया।
- विंध्य प्रदेश: संपूर्ण विंध्य प्रदेश को नए मध्य प्रदेश में मिला दिया गया।
- भोपाल राज्य: भोपाल राज्य को भी नए मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया।
- अन्य समायोजन: राजस्थान के सिरोंज उपखंड (जो पहले टोक रियासत का हिस्सा था) को मध्य प्रदेश में जोड़ा गया, जबकि मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा (भानपुरा तहसील) को राजस्थान को दिया गया।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

4.3 मध्य प्रदेश का जन्म इन सभी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, 1 नवंबर 1956 को एक नए और बड़े राज्य मध्य प्रदेश का गठन हुआ। भोपाल को इसकी राजधानी घोषित किया गया, जो पहले एक 'भाग स' राज्य था। इस नए राज्य में मध्य प्रांत और बरार के हिंदी भाषी क्षेत्र, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य शामिल थे। इस प्रकार, मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल के अनुसार) बना, जिसमें भाषाई रूप से हिंदी भाषी आबादी का बहुमत था।

5. एकीकरण और गठन के परिणाम एवं महत्व :

5.1 राजनीतिक स्थिरता और एकता: रियासतों का सफल एकीकरण और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का गठन राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसने भारत के भीतर विखंडन के किसी भी संभावित खतरे को समाप्त कर दिया और एक मजबूत संघीय ढांचा प्रदान किया।

5.2 प्रशासनिक दक्षता: विभिन्न और अव्यवस्थित रियासती प्रशासनिक प्रणालियों के स्थान पर एक एकीकृत और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, जिससे शासन और विकास कार्यों में अधिक दक्षता आई।

5.3 आर्थिक विकास का मार्ग: नवगठित राज्य ने संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और समन्वित विकास योजनाएँ बनाने का अवसर प्रदान किया। इसने विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं को कम करने में भी मदद की।

5.4 क्षेत्रीय पहचान और भाषाई सामंजस्य: भाषाई पुनर्गठन ने स्थानीय पहचान और संस्कृति को सम्मान दिया, जिससे लोगों में अपने राज्य और देश के प्रति अपनेपन की भावना बढ़ी। मध्य प्रदेश के मामले में, इसने एक बड़े हिंदी भाषी क्षेत्र को एक इकाई के रूप में एकजुट किया।

5.5 चुनौतियाँ: एकीकरण की प्रक्रिया चुनौतियों से भी खाली नहीं थी। विभिन्न रियासतों की अपनी कानून-व्यवस्था, कर प्रणाली और प्रशासनिक संरचनाएँ थीं, जिन्हें एक समान राष्ट्रीय

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

ढांचे में ढालना जटिल कार्य था। रियासती शासकों के विशेषाधिकारों और उनके पुराने दरबारियों के समायोजन में भी समय लगा।

6. निष्कर्ष :

रियासतों का एकीकरण और मध्य प्रदेश का गठन भारतीय इतिहास की एक असाधारण उपलब्धि है। यह सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके सहयोगियों की दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छाशक्ति और कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है, जिन्होंने भारत को एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र के रूप में आकार दिया। मध्य प्रदेश का गठन केवल कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को एक साथ लाने से कहीं अधिक था; यह विभिन्न संस्कृतियों, आर्थिक प्रणालियों और प्रशासनिक विरासत को एक सुसंगत इकाई में ढालने का एक महान प्रयास था। यह प्रक्रिया भारत की लोकतंत्र और एकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसने विविधता में एकता के सिद्धांत को सफलतापूर्वक स्थापित किया। आज का मध्य प्रदेश इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो भारत के केंद्र में स्थित होकर इसकी समृद्ध विरासत और आधुनिक प्रगति का प्रतीक बन गया है।

7. संदर्भ :

1. पटेल, सरदार वल्लभभाई. *भारत का पूर्ण एकीकरण*.
2. मेनन, वी.पी. *द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स*.
3. इंडिया गजटियर (विभिन्न खंड).
4. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, 1955.
5. विभिन्न ऐतिहासिक ग्रंथ एवं सरकारी दस्तावेज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राज्य पुनर्गठन पर।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मध्य प्रदेश में मानव बस्ती के सबसे शुरुआती प्रमाण: प्रागैतिहासिक काल का एक अवलोकन

Dr. Shalendra Kumar Goutam
NET, P.hd, Jiwaji University, Gwalior, M.P

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16645024

IMPACT FACTOR

5.924

Abstract

मध्य प्रदेश, अपने भौगोलिक केंद्र और विविध स्थलाकृति के कारण, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव बसावट के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक रहा है। यहां के पुरातात्विक स्थल, विशेषकर नर्मदा घाटी और विंध्य पर्वतमाला में, पुरापाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण काल तक मानव उपस्थिति और सांस्कृतिक विकास के निरंतर साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह शोधपत्र मध्य प्रदेश में मानव बस्ती के शुरुआती प्रमाणों की पड़ताल करता है, जिसमें विभिन्न प्रागैतिहासिक कालों के प्रमुख स्थलों, उनसे प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों और उनके महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

1. भूमिका :

मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसका पुरातात्विक महत्व अद्वितीय है। इसकी भौगोलिक स्थिति – उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम करना – तथा इसकी नदियाँ (नर्मदा, चंबल, बेतवा आदि) और पर्वतमालाएँ (विंध्य और सतपुड़ा) मानव जीवन के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करती थीं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मानव बस्ती के सबसे शुरुआती प्रमाण प्रागैतिहासिक काल (Prehistoric Period) से मिलते हैं, जो लाखों वर्षों पहले के मानव इतिहास को समेटे हुए हैं। इन प्रमाणों में पत्थरों के औजार, गुफा चित्रकला, आवास स्थल और बाद के चरणों में कृषि व धातु कर्म के साक्ष्य शामिल हैं।

2. प्रागैतिहासिक काल का विभाजन और मध्य प्रदेश में उसके प्रमाण :

मध्य प्रदेश में मानव बस्ती के प्रमाणों को मुख्य रूप से तीन प्रागैतिहासिक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

2.1. पुरापाषाण काल (Paleolithic Period) – लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक

यह मानव अस्तित्व का सबसे लंबा चरण है, जो मुख्य रूप से पत्थरों के अपरिष्कृत औजारों के उपयोग और आखेटक-संग्राहक जीवन शैली की विशेषता है। मध्य प्रदेश इस काल के साक्ष्यों से समृद्ध है।

- नर्मदा घाटी: यह क्षेत्र पुरापाषाण काल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
    - हाथनौरा (सिहोर जिला): यहां से 1982 में पुरातत्वविद् अरुण सोनकिया द्वारा *होमो इरेक्टस* प्रजाति के मानव कपाल का जीवाश्म "नर्मदा मानव" (Narmada Man) खोजा गया था। यह भारत में मिला मानव जीवाश्म का एकमात्र ज्ञात प्रमाण है, जो इस बात का सूचक है कि इस क्षेत्र में लाखों वर्ष पहले आदिमानवों का निवास था। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के पाषाण उपकरण (हस्त-कुल्हाड़ी, क्लीवर, चापर) भी मिले हैं।
    - महेश्वर, मंडलेश्वर, नेमावर: नर्मदा नदी के किनारे ये स्थल निम्न और मध्य पुरापाषाण काल के औजारों के लिए जाने जाते हैं।
- भीमबेटका (रायसेन जिला): यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भीमबेटका शैल आश्रय (Rock Shelters) पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक मानव अधिवास के निरंतर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।
    - यहां से निम्न पुरापाषाण काल के बड़े फलक वाले औजार (जैसे हस्त-कुल्हाड़ी) और मध्य पुरापाषाण काल के छोटे और नुकीले औजार पाए गए हैं। ये औजार शिकार के लिए उपयोग किए जाते थे।

- **आदमगढ़ पहाड़ियाँ (होशंगाबाद जिला): यहां से मध्य पुरापाषाण काल के औजारों की बड़ी संख्या मिली है, जो मानव बस्ती की पुष्टि करती है।**

2.2. मध्यपाषाण काल (Mesolithic Period) – लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक

यह काल पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच एक संक्रमणकालीन चरण था। इस काल में सूक्ष्म पाषाण औजारों (Microliths) **का उपयोग बढ़ा और मानव जीवन शैली में कुछ बदलाव आए।**

- **भीमबेटका (रायसेन जिला): मध्यपाषाण काल के लिए भीमबेटका सबसे महत्वपूर्ण स्थल है।**
    - **यहां से बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण औजार** (**छोटे ब्लेड, त्रिकोण, समलम्ब**) **मिले हैं, जो तीर-कमान जैसे उपकरणों के साथ उपयोग किए जाते थे।**
    - **यहां की विश्व प्रसिद्ध शैल चित्रकला** (Rock Paintings) **भी मुख्य रूप से मध्यपाषाण काल से संबंधित है, जो उस समय के मानव की कलात्मक अभिव्यक्ति, दैनिक जीवन, शिकार दृश्यों और पशु-मानव संबंधों को दर्शाती है। ये चित्रकलाएँ मानव बस्ती के कलात्मक और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण हैं।**
- **आदमगढ़ (होशंगाबाद जिला): भीमबेटका की तरह, आदमगढ़ से भी बड़ी संख्या में सूक्ष्म पाषाण औजार और शैल चित्र पाए गए हैं।**
    - **यहां से पशुओं के शुरुआती पालतूकरण** (**जैसे कुत्ता, गाय-बैल**) **के भी अप्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, जो मानव बस्ती के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था।**
- **अन्य स्थल: पचमढ़ी के पास जटाशंकर, सागर के पास एरण, मंदसौर के पास शैल आश्रय भी मध्यपाषाण काल के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।**

2.3. नवपाषाण काल (Neolithic Period) – लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

यह काल कृषि, पशुपालन, स्थायी बस्तियों और मृद्भांड निर्माण की शुरुआत के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में शुद्ध नवपाषाण स्थलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और अक्सर यह ताम्रपाषाण संस्कृति के साथ विलीन हो जाता है।

- कुछ पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस काल के अंत तक प्रारंभिक कृषि और स्थायी बस्तियों का विकास शुरू हो गया था।
- नर्मदा घाटी के कुछ क्षेत्रों में प्रारंभिक मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं जो नवपाषाण काल के अंतिम चरण या ताम्रपाषाण काल के प्रारंभिक चरण से संबंधित हो सकते हैं।

2.4. ताम्रपाषाण काल (Chalcolithic Period) – लगभग 2,300 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक

यह वह काल था जब मानव ने पत्थरों के औजारों के साथ-साथ तांबे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। इस काल में स्थायी ग्राम बस्तियों का विकास हुआ, जो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से समृद्ध रहे हैं।

- कायथा (उज्जैन जिला) : यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी ताम्रपाषाण संस्कृति (कायथा संस्कृति) का प्रतिनिधित्मक स्थल है, जिसका काल लगभग 2300-2000 ईसा पूर्व है।
  - यहां से सुनियोजित ग्रामीण बस्तियों, विशिष्ट गहरे लाल रंग के चित्रित मृद्भांड (Kayatha Ware), तांबे के उपकरण, मनके और हड़प्पा संस्कृति के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं।
- एरण (सागर जिला) : बेतवा नदी के किनारे स्थित यह स्थल लगभग 2000-700 ईसा पूर्व की ताम्रपाषाण संस्कृति को दर्शाता है।
  - यहां से किलेबंदी वाली बस्तियों, विभिन्न प्रकार के मृद्भांड (मालवा वेयर, अहार वेयर), तांबे की वस्तुएं, मनके और कृषि गतिविधियों के साक्ष्य मिले हैं।
- नागदा (उज्जैन जिला) : चंबल नदी के किनारे स्थित यह एक और महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल है, जो लगभग 1600-1300 ईसा पूर्व का है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

    - यहां से मिट्टी के घर, अनाज के गड्ढे, तांबे के उपकरण और विशिष्ट मालवा वेयर मृद्भांड मिले हैं।
- अन्य महत्वपूर्ण स्थल: महेश्वर (खरगोन), नवदाटोली (खरगोन), आवरा (मंदसौर) और दांगवाड़ा (उज्जैन) भी ताम्रपाषाणकालीन मानव बस्तियों के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, जहां से कृषि के अवशेष, विभिन्न प्रकार के मृद्भांड और धातु उपकरण मिले हैं।

3. प्रमुख स्थलों का महत्व

- भीमबेटका: यह स्थल केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर मानव उत्पत्ति और कलात्मक विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यहां एक ही स्थान पर पुरापाषाण से लेकर ऐतिहासिक काल तक की मानवीय गतिविधियों के निरंतर साक्ष्य एक अनूठा पुरातात्विक रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। वी.एस. वाकणकर का यहां का कार्य मील का पत्थर है।
- नर्मदा घाटी: नर्मदा मानव की खोज ने भारत में मानव विकासवादी अध्ययन को एक नई दिशा दी और इस क्षेत्र को वैश्विक पुरातात्विक मानचित्र पर स्थापित किया।
- ताम्रपाषाण स्थल: कायथा, एरण और नागदा जैसे स्थल मध्य भारत में ग्रामीण जीवन के उदय, प्रारंभिक कृषि समाज, धातु विज्ञान के विकास और व्यापारिक नेटवर्क की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

4. निष्कर्ष

मध्य प्रदेश में मानव बस्ती के सबसे शुरुआती प्रमाण निस्संदेह प्रागैतिहासिक काल से मिलते हैं। पुरापाषाण काल की नर्मदा घाटी में आदिमानव जीवाश्मों और भीमबेटका में सबसे पुराने पाषाण औजारों से लेकर मध्यपाषाण काल की शैल चित्रकला और सूक्ष्म पाषाण औजारों तक, तथा ताम्रपाषाण काल की सुनियोजित ग्रामीण बस्तियों तक, यह क्षेत्र मानव इतिहास के विभिन्न चरणों का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। इन पुरातात्विक खोजों ने केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता के उद्भव और विकास को

समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह प्रमाणित होता है कि मध्य प्रदेश आदिकाल से ही मानव बसावट और सांस्कृतिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

5. संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण** (Archaeological Survey of India) **की विभिन्न रिपोर्टें।**
2. **वाकणकर, वी.एस.** (V.S. Wakankar) **और ब्रुक्स, आर.आर.आर.** (R.R.R. Brooks)**।** ***स्टोन एज पेंटिंग्स इन इंडिया।***
3. **सांकलिया, एच.डी.** (H.D. Sankalia)**।** ***प्रीहिस्टरी एंड प्रोटोहिस्टरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान।***
4. **तिवारी, शिव कुमार।** ***मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं कला विरासत।***
5. **एनसीईआरटी** (NCERT) **और अन्य प्रामाणिक भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तकें।**
6. **विभिन्न पुरातात्विक जर्नलों और मोनोग्राफ्स में प्रकाशित शोध पत्र।**

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

1857 का स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका

Dr. Shalendra Kumar Goutam
NET, P.hd, Jiwaji University,
Gwalior, M.P

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI
https://doi.org/10.5281/zenodo.16645362

IMPACT FACTOR
5.924

परिचय

1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे अक्सर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यद्यपि इसका केंद्र मुख्य रूप से उत्तरी भारत के दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और झाँसी जैसे क्षेत्र माने जाते हैं, परंतु इस विद्रोह की लहरें मध्य भारत, विशेषकर वर्तमान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक भी फैली थीं। मध्य प्रदेश, अपनी भौगोलिक स्थिति और विविध रियासतों, जनजातीय समुदायों तथा सैन्य छावनियों के कारण, इस महासंग्राम में एक महत्वपूर्ण और अक्सर उपेक्षित भूमिका निभाता है। इस आलेख में हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के योगदान, इसके प्रसार और प्रमुख व्यक्तित्वों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

विद्रोह के कारण और मध्य प्रदेश पर प्रभाव

1857 के विद्रोह के मूल में ब्रिटिश नीतियों का गहरा असंतोष था। लॉर्ड डलहौजी की 'व्यपगत का सिद्धांत' (Doctrine of Lapse), जिसके तहत उत्तराधिकारी विहीन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, ने कई रियासतों, जैसे झाँसी (जो भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश से सटा हुआ था और जिसके संघर्ष का प्रभाव मध्य प्रदेश पर पड़ा) और सतारा, नागपुर आदि में भय और आक्रोश पैदा किया। आर्थिक शोषण, भू-राजस्व नीतियों, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, और धार्मिक-सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप ने भी जनता में व्यापक असंतोष पैदा किया।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मध्य प्रदेश में भी ये कारक सक्रिय थे:

1. **रियासतों का असंतोष: कई रियासतें ब्रिटिश हस्तक्षेप से त्रस्त थीं।**
2. **सैन्य छावनियां: महू, नीमच, सीहोर, जबलपुर जैसे स्थानों पर ब्रिटिश भारतीय सेना की छावनियां थीं, जहाँ चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने सिपाहियों को भड़काया।**
3. **जनजातीय विद्रोह: ब्रिटिश नीतियों ने जनजातीय समुदायों की पहचान, भूमि और वन अधिकारों पर हमला किया, जिससे उनमें पहले से ही असंतोष पनप रहा था।**
4. **स्थानीय नेतृत्व: अनेक छोटे राजाओं, जमींदारों और जागीरदारों ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने या वापस पाने के लिए विद्रोह में भाग लिया।**

मध्य प्रदेश में विद्रोह का स्वरूप और प्रसार :

मध्य प्रदेश में 1857 **का विद्रोह विभिन्न रूपों में सामने आया, जिसमें सैन्य विद्रोह, रियासती प्रतिरोध और जनजातीय आंदोलन शामिल थे:**

1. **मालवा क्षेत्र:**
   - **नीमच:** 3 **जून** 1857 **को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क उठा। यहाँ के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर छावनी को अपने कब्जे में ले लिया।**
   - **महू और इंदौर: जुलाई** 1857 **में महू में भी सैन्य विद्रोह हुआ। इंदौर में सआदत खान के नेतृत्व में होलकर सेना के सैनिकों ने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। यद्यपि होलकर शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, पर उनकी सेना और आम जनता में असंतोष व्याप्त था। यह हमला ब्रिटिश सत्ता के लिए एक गंभीर चुनौती था।**
   - **धार और अमझेरा: धार में राजा बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और उन्हें फाँसी दी गई।**

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- मंदसौर: यहाँ फिरोज शाह (दिल्ली के मुगल शहजादे) ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें स्थानीय सैनिक और जनजातीय लोग शामिल थे।

2. बुंदेलखंड क्षेत्र (सागर, दमोह, जबलपुर):
   - यह क्षेत्र विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। सागर और दमोह में विद्रोह लंबे समय तक चला। सागर में अंग्रेजों को घेराबंदी का सामना करना पड़ा।
   - जबलपुर: 1857 का सबसे हृदय विदारक और प्रेरणादायी अध्याय जबलपुर से जुड़ा है। गौंड राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। अपनी कविताओं और संदेशों के माध्यम से उन्होंने लोगों को संगठित किया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर 18 सितंबर 1857 को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। यह घटना समूचे महाकौशल क्षेत्र के लिए प्रेरणास्रोत बनी।
   - नरसिंहपुर, मंडला और सिवनी: इन क्षेत्रों में भी स्थानीय जमींदारों और जनजातीय नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। मंडला में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष किया।
3. ग्वालियर और तात्या टोपे का अभियान:
   - ग्वालियर यद्यपि सिंधिया शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, पर उनकी सेना और जनता में विद्रोह की भावना प्रबल थी। रानी लक्ष्मीबाई के झाँसी से निकलने के बाद, वे तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पहुँचीं।
   - तात्या टोपे: 1857 के संग्राम के सबसे गतिशील और जुझारू नेताओं में से एक तात्या टोपे ने मध्य प्रदेश की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाया। झाँसी के पतन के बाद, उन्होंने बुंदेलखंड और मालवा में छापामार युद्ध का संचालन किया। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया और सिंधिया को भागने पर मजबूर किया। उन्होंने चंदेरी, सागर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर, धार और राजगढ़ सहित मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में ब्रिटिश सेना को लगातार चुनौती दी। उनकी गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध रणनीति ने अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान रखा।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

4. निमाड़ और जनजातीय विद्रोह:
    - मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र (पश्चिमी मध्य प्रदेश) में भील समुदाय ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किया।
    - भीमा नायक: पश्चिमी निमाड़ में भीमा नायक ने भीलों को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लंबे समय तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे।
    - खाज्या नायक: सेंधवा के पास खाज्या नायक ने भी भीलों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया।
    - इन नायकों ने ब्रिटिश संचार लाइनों को बाधित किया और छापामार हमलों से अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया।

मध्य प्रदेश में विद्रोह के महत्वपूर्ण नेता:

1. रानी लक्ष्मीबाई: यद्यपि उनका राज्य झाँसी (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में था, ग्वालियर उनके संघर्ष का अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहाँ उन्होंने वीरगति प्राप्त की।
2. तात्या टोपे: उन्होंने ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, सागर आदि में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध का संचालन किया।
3. राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह: जबलपुर के गौंड शासक, जिन्हें अंग्रेजों ने तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया।
4. रानी अवंतीबाई लोधी: रामगढ़ (मंडला) की रानी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया।
5. सआदत खान: इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने वाले होलकर सेना के नेता।
6. भीमा नायक और खाज्या नायक: निमाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी नेता।
7. राजा बख्तावर सिंह: धार और अमझेरा क्षेत्र के विद्रोही नेता।
8. शेर शाह: मंदसौर में जिन्होंने अपनी सरकार स्थापित की।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

विद्रोह का महत्व और परिणाम :

मध्य प्रदेश में हुए 1857 के विद्रोह का अपना विशिष्ट महत्व है:

- **व्यापकता:** इसने दर्शाया कि विद्रोह केवल ऊपरी गंगा के मैदान तक सीमित नहीं था, बल्कि मध्य भारत के दूरदराज के क्षेत्रों और विविध समुदायों (क्षत्रिय राजाओं, मराठा सरदारों, जनजातियों, सैनिकों) तक फैला हुआ था।
- **जनजातीय भागीदारी:** भील और गोंड जैसे आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने विद्रोह को एक व्यापक सामाजिक आधार दिया, जो ब्रिटिश नीतियों के प्रति उनकी गहरी नाराजगी को दर्शाता है।
- **रणनीतिक महत्व:** मध्य प्रदेश की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति ने इसे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया। तात्या टोपे जैसे नेताओं ने इस क्षेत्र का उपयोग अपनी रणनीतिक गतिविधियों के लिए किया, जिससे अंग्रेजों को उन्हें नियंत्रित करने में काफी कठिनाई हुई।
- **बलिदान की गाथाएं:** शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान, अमझेरा और धार के राजाओं का संघर्ष, तथा रानी अवंतीबाई का शौर्य – ये सभी मध्य प्रदेश के लिए स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथाएँ बन गए।

यद्यपि मध्य प्रदेश में विद्रोह को अंततः अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, परंतु इसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया। कई रियासतों के शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे (जैसे सिंधिया, भोपाल की बेगम), जिससे अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में सहायता मिली। हालांकि, जनता और सैनिकों का असंतोष स्पष्ट था।

निष्कर्ष :

1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है और इसमें मध्य प्रदेश की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। यहाँ के स्थानीय राजाओं, जमींदारों, सैनिकों और विशेष रूप से जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष किया। रानी लक्ष्मीबाई का ग्वालियर तक का अभियान, तात्या टोपे की

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

अंतहीन छापामार लड़ाई, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान, तथा भीमा नायक व खाज्या नायक की जनजातीय प्रतिरोध की गाथाएँ मध्य प्रदेश को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं। यह संघर्ष न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक चुनौती थी, बल्कि इसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए भी प्रेरणा का काम किया, यह साबित करते हुए कि पूरे भारतवर्ष में मुक्ति की ज्वाला प्रज्वलित थी।

संदर्भ :

1. मध्य प्रदेश का इतिहास (विभिन्न लेखकों द्वारा)
2. भारत का स्वतंत्रता संग्राम (विभिन्न लेखकों द्वारा, जैसे विपिन चंद्रा)
3. मध्य प्रदेश गजेटियर
4. स्थानीय इतिहास और शोध पत्र
5. ब्रिटिश अभिलेखागार (जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया)

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

The Role of Language Proficiency in Enhancing Entrepreneurial Opportunities and Economic Empowerment : A Business Management perspective

RASHI GHADGE

Assistant Professor, Malwa Institute of Science and Technology, Sanwar Road, Indore, (M.P.)

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16688887

IMPACT FACTOR

5.924

Abstract

Language plays a pivotal role in enabling economic inclusion and empowerment across the world. By lowering communication barriers, multilingual approaches in business and finance allow marginalized populations to access markets, services, and knowledge. This paper examines how using regional languages in marketing and branding strengthens local engagement, how multilingual communication enhances business operations, and how training and financial literacy programs delivered in local languages increase participation in the economy. We draw on case studies from India, Nigeria, Ghana, the U.S., and other regions to illustrate these effects. Marketing campaigns tailored to local languages (e.g. Coca-Cola's "We All Understand Coke") and platforms like Netflix show how brands build trust by communicating in native tongues. In business communication, platforms and apps localized into vernaculars expand reach (e.g. India's Hindi-speaking market). MSME (Micro/Small enterprise) training in local languages (e.g. vocational programs in Ghana and India) has improved uptake and skills. Financial institutions, from U.S. banks to Indian fintechs, report higher engagement when services and literacy materials are available in consumers' own languages. We also discuss challenges – such as translation costs, maintaining quality, and technology integration – alongside opportunities offered by digital tools and regulatory support. The evidence suggests that language-sensitive strategies significantly expand economic opportunities for underserved communities worldwide.

Key Words:- Financial Regulators, Multilingual, leveraging language, financial literacy, : ATDC (Apparel Training & Design Centre), UNESCO

Introduction:

Language is fundamental to human development and inclusive growth. UNESCO notes that *"indigenous languages matter for sustainable development, good governance, reconciliation and peace building".

Language is a" fundamental precondition to human development": it enables people to communicate, share knowledge, and participate fully in society. Conversely, language barriers can exclude groups from economic life. Around 40% of the world's ~6,700 languages are endangered, threatening the cultural and knowledge systems they carry. Increasingly, policymakers and businesses recognize that safeguarding linguistic diversity is not merely cultural preservation but a powerful enabler of inclusive economic development.

In a globalized economy, access to information and services in one's native language is closely tied to economic inclusion. For example, India's economy—now the 5th-largest in the world—illustrates this link. Over 44% of Indians have Hindi as a mother tongue and demand for Hindi content (75% of videos viewed) far exceeds other languages. Yet English interfaces remain common. As Bajaj Finserv observes, "millions of new-to-digital users in rural India…prefer to engage in their native languages", and English-only interfaces often deter them from using financial services. Bridging this language gap is now seen as essential: providing products, marketing and education in local languages drives user engagement, fosters trust, and eliminates barriers that have historically excluded large segments of the population. Similarly, in the United States, roughly 26 million people speak English "less than very well," which led financial regulators to push banks toward multilingual customer service.

This paper explores how language use drives economic empowerment. We first examine the role of marketing and branding in regional languages, showing how localized messaging builds brand affinity and market reach. Next, we consider business communication in multilingual contexts, including internal operations and customer interactions. We then analyze MSME training and skilling in local languages, highlighting how vernacular instruction boosts skills uptake. Finally, we review financial literacy and consumer rights delivered in vernacular mediums, showing how language-sensitive education and disclosures promote inclusion. Each section draws on global examples and data, and discusses both opportunities and challenges in leveraging language for economic progress.

Marketing and Branding in Regional Languages:

Global brands and local businesses alike have found that tailoring marketing to regional languages and cultures significantly improves resonance with customers. Studies show that "strategic use of language in branding helps brands make meaningful connections, convey their values effectively, and adapt to changing market dynamics", leading to greater brand success. In practice, this means using local-language slogans, culturally relevant imagery, and region-specific campaigns. For example, Coca-Cola's recent campaign "We All Understand Coca-Cola" dramatizes overcoming language barriers: stories of strangers from different language backgrounds sharing Coke emphasize that "sharing a Coca-Cola is a universal language that we all understand". The campaign explicitly features conversations written in both Latin scripts (Spanish, French, German) and non-Latin scripts (Dhivehi, Sindhi, Urdu) merging into Coke's bottle silhouette. This demonstrates how a brand can harness the power of local languages to communicate a universal message.

Other brands have localized content to target specific markets. Netflix, for instance, offers dubbed/subtitled content and region-tailored marketing in dozens of countries. By analyzing local viewing habits and

creating culturally accurate promotions, Netflix “allows consumers to feel understood by this brand”. Similarly, KFC created a South African campaign with buckets featuring local illustrator Karabo Poppy’s artwork; combined with regionally flavored menus, this built goodwill by showing understanding of local audiences. As one analyst noted, “the shift from ‘reach’ to ‘relevance’ urges more brands to use localized marketing”, avoiding the mistakes of campaigns that simply offend or miss the mark in a foreign culture. These efforts underscore that localization is not just translation of text, but adaptation of the full brand narrative to local context.

Opportunities: Local-language marketing can significantly increase brand loyalty and customer acquisition. Consumers are more likely to engage with ads and content in their mother tongue, as familiarity breeds trust. For emerging markets (e.g. rural India or Mexico), vernacular advertising has tapped underserved audiences. A striking example: the Indian food-delivery platform Zomato saw over 150,000 monthly orders come through regional-language interfaces by late 2022, with Hindi users alone accounting for 54% of all orders. This suggests localized marketing directly translates to revenue. Furthermore, culturally tuned branding helps companies align with local festivals and values, strengthening emotional connection.

Challenges: Creating multilingual marketing is resource-intensive. Brands must invest in quality translation, native speakers, and local creative talent. There is risk in mis-translations or cultural faux pas that can alienate consumers. Managing brand consistency across many languages also requires careful governance. Finally, smaller businesses may lack budgets for extensive localization. Nevertheless, many see the return on investment as worthwhile.

In summary, the evidence indicates that marketing and branding in local languages drive inclusion by bringing consumers into the economic fold. As Musonda and Siame (2025) conclude, language-savvy brands “make meaningful connections” with diverse audiences. Case studies from Coca-Cola, Netflix, KFC and others illustrate that culturally and linguistically aware campaigns enhance market presence globally.

Business Communication in Multilingual Contexts:

Business operations increasingly span multiple languages – both internally among staff and externally with customers and partners. In multinational settings, bridging language gaps is crucial to efficiency and growth. For example, in markets like India, English remains a common business language, but a significant portion of employees and consumers are more proficient in local languages like Hindi, Tamil or Bengali. As one industry commentator notes. English has been widely used in business communication, [but] Hindi still remains a driving force in communicating with a significant population. In fact, India now has the world’s third-largest number of Hindi speakers (~610 million), and its share of internet users is rapidly growing. Companies expanding into India are increasingly adopting Hindi (and other vernacular) in operations to reach the “next billion” users.

Concrete examples show the business impact. Zomato’s success in Hindi illustrates that adapting a company’s interface and support in local languages can vastly widen its user base. Similarly, Alibaba’s e-commerce platforms offer multilingual customer service to handle diverse buyer questions globally. Within

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

companies, multilingual training and documentation can boost productivity: ATDC (Apparel Training & Design Centre) in India found that switching to instructors fluent in regional languages greatly improved MSME skill training outcomes. In healthcare, banks and BPOs hiring bilingual staff report higher customer satisfaction when clients speak to a teller or agent in their native language. Thus, multilingual communication is not just courtesy but a competitive business strategy.

Key considerations in multilingual business communication include:

Staff training: Employers often offer language training to employees. Language programs by companies like Rosetta Stone or by governments (e.g. China's foreign language curriculum for export industries) aim to equip workers for international trade. Bilingual staff serve as invaluable links; the U.S. Consumer Finance Bureau notes that banks find "hiring of bilingual staff at branches and call centers…particularly effective for customer engagement", often yielding "more bang for the buck" than pure document translation.

Technology solutions: Advances in translation tech (AI-driven chatbots, speech-to-text, multilingual CRMs) are easing communication barriers. For instance, voice-first interfaces in local languages are emerging for users with limited literacy. Mobile apps increasingly support content toggling across languages. Globalization has turned multilingual support from an aspiration into a necessity in many sectors.

Market expansion: Companies that ignore local languages risk alienating consumers. Conversely, those who adapt can tap underserved markets. As Reverie points out, smartphone penetration in India's Tier-2/3 cities has put native languages "at the forefront of business communication," enabling firms to capture a huge untapped market. In effect, speaking the customer's language – literally – can be a powerful sales and inclusion tool.

Challenges in multilingual business communication include the cost and logistics of translation and interpretation, varying literacy levels, and legal requirements. For example, the European Union has 24 official languages, requiring businesses to translate certain product information or legal notices. In many African countries (Nigeria has over 500 languages), companies often rely on lingua francas (e.g. English, Swahili) but still need to address local language needs for depth. Ensuring message consistency and cultural appropriateness across languages requires robust processes. Nonetheless, the business case is clear: accommodating language diversity can significantly lower entry barriers and enable organizations to engage new workers and consumers, driving economic inclusion.

MSME Training and Skilling in Local Languages:

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) form a large part of many economies, and skill development among their owners and employees is critical for growth. Delivering training in the local language of trainees has been shown to greatly enhance understanding and empowerment. In rural Ghana, for example, an informal-sector training program found that instruction in local languages (translated manuals by native instructors) was "successful" in teaching illiterate trainees new vocational skills.

Similarly, in India's textile sector, training organizations deliberately employed local instructors and "started giving training in local languages" alongside soft skills. This switch led to better comprehension and higher productivity.

Case studies around the world confirm the pattern. UNESCO and NGOs often advocate mother-tongue or local-language education in vocational programs to ensure inclusivity. In Ethiopia, agricultural extension and MSME workshops are often taught in Amharic or Oromo so that farmers and entrepreneurs can grasp technical concepts. In Bangladesh, government and NGO trainers provide mobile workshops in rural Bengali dialects on tailoring or carpentry skills. These programs report higher enrollment and retention than similar courses in non-native languages.

Opportunities: Local-language skilling lowers the threshold for participation. When people learn in a language they fully understand, they acquire skills more quickly and confidently. This is especially important in communities with low literacy in national or international languages. By empowering local entrepreneurs with training in their mother tongue, economic initiatives can spread more evenly. For women and youth in particular, vernacular education is often more accessible. For instance, in India's decentralized "cluster-based" training models, integrating local language materials has helped MSMEs upgrade technologies (e.g. weaving, food processing) in a culturally relevant way. Digitally, e-learning platforms now offer multilingual content – so a micro-entrepreneur can watch a tutorial video on smartphone repairs in her regional language.

Challenges: Developing high-quality training content in every local language is resource-intensive. Governments and organizations must invest in translation of curricula, dictionaries of technical terms, and training of trainers who are fluent in local tongues. In some cases, multiple dialects exist in one area, complicating design. There is also the risk of inconsistent quality if informal translators are used. Furthermore, measuring outcomes can be harder if assessment tools are not standardized across languages. Digital tools (AI translators, localized apps) can help but may not capture nuances or require smartphone access.

Despite these challenges, the push for vernacular skill training is growing. International development agencies increasingly incorporate local languages into workforce development projects. For example, the ILO and World Bank have promoted community-based vocational training where instructions are given in the trainees' language. By aligning skill-building with learners' linguistic context, such programs drive inclusive economic empowerment – equipping individuals to start businesses or earn higher incomes without the language barrier.

Financial Literacy and Consumer Rights in Vernacular Mediums:

Financial empowerment – the ability to access, understand and use financial services – strongly depends on language access. Across the globe, many low-income or rural individuals are excluded from banking and credit simply because they cannot navigate financial jargon in a dominant language. Recognizing this, financial regulators and institutions have begun delivering literacy and consumer-rights information in vernacular languages.

In the United States, for instance, the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) reports that 26 million Americans speak English "less than very well," creating an underserved market for banks. As a result, many institutions are expanding capacity to serve customers "in languages other than English", driven by business needs to reach demographic segments. The CFPB notes that banks are launching multilingual programs (translated agreements, disclosures, digital platforms) and hiring bilingual staff to connect with limited-English populations. Bilingual personnel at branches and call centers allow personalized assistance: customers receive help in a language they understand, which dramatically improves uptake of financial products. These steps not only comply with fair-lending regulations but also directly foster financial inclusion.

In emerging markets, vernacular financial education is often even more critical. In India, Bajaj Finserv highlights that millions of first-time rural digital users are more comfortable learning about banking and insurance in their native languages. Banks and fintechs in India now provide mobile banking apps and IVRs in Hindi and other regional languages, and partner with local influencers to teach financial concepts contextually. For example, chatbots and AI voice assistants answer basic banking queries in Tamil, Telugu, and other tongues. Regulators have also mandated language inclusivity: key documents (loan agreements, terms and conditions) must be made available in languages that consumers understand easily. The net effect is an expanding customer base – banks that were once English-only now report growth from "Bharat" consumers who transact in their mother tongue.

In Nigeria, grassroots advocates argue that financial literacy efforts must use local languages. Analysts note that nearly half of Nigeria's adults are financially excluded, often in rural areas where English is not well understood. They propose that holding seminars and workshops in Hausa, Igbo, Yoruba or other local dialects would dramatically improve comprehension. As one report observes: "Using local languages puts the people at an advantage. The topic-specific words are far simpler to comprehend in one's own language… The goal is to make people financially literate; therefore using their local languages would be most sensible". Likewise, training sessions for farmers on savings, credit, and government schemes are far more effective when delivered in native languages. In practice, some microfinance NGOs now recruit local teachers and produce vernacular brochures and radio dramas about budgeting and rights.

Opportunities: Vernacular financial education builds trust and confidence. People are more likely to use savings accounts or loans when they fully understand the terms. This expands the formal financial system and empowers households to make informed decisions. Tailored messaging also respects cultural contexts (e.g. avoiding taboo topics) to reach marginalized groups. Furthermore, when consumers can read contracts and disclosures in their language, they are better protected from predatory practices, strengthening consumer rights.

Challenges: Ensuring accuracy of financial translations is complex, since many technical terms have no direct equivalent. Quality control and consistent terminology are needed to prevent misunderstanding. Also, reaching illiterate or semi-literate populations requires multimedia approaches (audio, video) rather than text. Institutions face cost challenges in producing materials across multiple languages, especially if markets are small. Finally, regulation enforcement is uneven: some jurisdictions still default to major languages,

inadvertently excluding minorities. For example, South Africa's 11 official languages mandate multilingual public communications, but compliance varies.

Overall, it indicate that language-inclusive finance initiatives increase economic empowerment. The CFPB found that banks view multilingual services as a growth strategy, not just compliance, to *"better serve existing clientele and connect specific consumer populations with products tailored to their needs"*. Bajaj Finserv reports that vernacular financial content – from regional-language blogs to AI-generated FAQs – helps "users understand complex financial concepts in an accessible, culturally relevant" way. These findings suggest that providing financial literacy and rights information in vernaculars can significantly boost inclusion, though it requires commitment of resources and innovative delivery methods.

Literature Review:

According to UNESCO (2021), indigenous languages are integral to sustainable development and human empowerment. Language barriers can marginalize populations from economic opportunities, especially in regions with low literacy in dominant or official languages.

Research by Akindele (2014) emphasizes that financial literacy is best delivered in local languages, especially in rural and developing contexts. When individuals understand economic concepts in their mother tongue, they are more likely to engage with formal financial institutions and services.

Jain and Sanghi (2016) note that in rural India, a large proportion of digital users prefer interfaces and services in regional languages. Startups and MSMEs that adopt vernacular strategies see better adoption and retention among local customers.

Furthermore, Musonda and Siame (2025) show that language used in branding and marketing can shape consumer trust and perception. Language-localized marketing campaigns have been successful in engaging underserved communities, especially where English or dominant-language literacy is low.

Koshy (2021) highlighted the importance of delivering MSME training in local languages to improve participation, particularly among women and youth. Localized training ensures that participants not only understand the content but are also empowered to apply it confidently.

Problem Statement:

Many aspiring entrepreneurs, especially in developing economies or multilingual regions, face barriers due to limited language skills, which can hinder business success and economic mobility.

Research Objective:

To explore how language proficiency enhances entrepreneurial success

To explore how language proficiency contributes to individual and community economic empowerment.

Research Methodology:

Research Design:

This study adopts a descriptive and exploratory research design to analyze the relationship between language proficiency and economic empowerment through entrepreneurial avenues. The descriptive component focuses on the current state of multilingual strategies in business, while the exploratory aspect investigates how regional and local language usage influences entrepreneurship, business inclusion, and access to financial and training services.

Research Approach:

A qualitative research approach is utilized, incorporating case studies, document analysis, and secondary data from reports, institutional publications, and existing literature. This approach allows a deep and contextual understanding of how language impacts various dimensions of business activity and empowerment, especially in multilingual and developing regions.

Conclusion:

Language is not merely a medium of culture; it is a driver of economic empowerment. By enabling access to markets, services, and knowledge, local languages open opportunities for billions of people. Throughout this paper, we have seen that marketing products and branding in regional languages creates relevance and trust among local consumers. In multilingual business environments, companies that invest in local-language communication – through bilingual staff, translated platforms, or localized content – can tap into underserved markets and improve internal coordination. Crucially, when vocational training and financial education are offered in vernacular languages, poorer and rural communities gain new skills and agency that lead to entrepreneurship and financial well-being.

These benefits are clear, yet challenges remain. Developing and managing multilingual content requires significant resources and planning. Ensuring quality translation, cultural nuance, and technical accuracy is complex. Technology can help – for instance, voice-based AI systems and real-time translators are emerging to support vernacular access. Policymakers also play a role: regulations mandating language inclusivity (as seen in the CFPB guidance and Indian financial rules) create incentives for businesses to accommodate language diversity.

Looking forward, digital transformation holds promise. The rise of generative AI allows instant, scalable production of regional-language content, from chatbots to video explainers. Mobile connectivity means even remote users can access localized apps. But to fully leverage these tools, the human dimension is key: indigenous leadership and grassroots input must guide efforts, ensuring that languages are used authentically and education materials meet community needs. UNESCO emphasizes that indigenous communities themselves should drive language preservation for sustainable development.

In conclusion, the evidence suggests that embracing linguistic diversity is essential for inclusive economic growth. By speaking the languages of their audiences, businesses and educators can unlock talents and

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

markets that might otherwise remain untapped. Economic empowerment thus flows not only from capital and technology, but also from the simple act of communication – giving every person the power to participate in prosperity, in the language they know best.

References:

1. Bajaj Finserv. (2024). Vernacular: Speaking Your Language. Powering Your Financial Journey. [Marketing article]. Retrieved from https://www.aboutbajajfinserv.com/ticc/ai-speaking-your-language
2. Consumer Financial Protection Bureau. (2025, January 15). What We're Watching: Language Access in Consumer Finance. CFPB Blog. Retrieved from https://www.consumerfinance.gov/about-us/blog/what-were-watching-language-access-in-consumer-finance/
3. International Labour Organization. (2002). Training for Work in the Informal Sector in Ghana. ILO.
4. Jain, N., &Sanghi, K. (2016, August 10). The Rising Connected Consumer in Rural India. Boston Consulting Group. Retrieved from https://www.bcg.com/publications/2016/globalization-customer-insight-rising-connected-consumer-in-rural-india
5. Koshy, D. O. (2021, April 5). RUNway to Skilled India. National Skills Network (interview). Retrieved from https://nationalskillsnetwork.in/runway-to-skilled-india/
6. Musonda, N., &Siame, P. (2025). The impact of language on branding: A comprehensive analysis. Linguistic Exploration, 2(1), 37–46.
7. Reverie Inc. (2024, January 17). Translate To Hindi: A Strategy For Business Growth in 2024. Retrieved from https://reverieinc.com/blog/translate-to-hindi-a-strategy-for-business-growth-in-2024/
8. UNESCO. (2021). The International Year of Indigenous Languages. UNESCO. Retrieved from https://www.unesco.org/en/articles/international-year-indigenous-languages
9. This Campaign Symbolises the Universal Understanding of Coca-Cola (2025, May 2). LBBOnline. Retrieved from https://lbbonline.com/news/this-campaign-symbolises-the-universal-understanding-of-coca-cola
10. Akindele, P. (2014, January 24). Local Languages to Promote Financial Literacy. Legalnaija. Retrieved from https://legalnaija.com/local-languages-to-promote-financial/

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

जंक फूड एक अभिशाप : स्वास्थ्य के संदर्भ में

उषा गुप्ता
शोधार्थी (गृह विज्ञान)
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

डॉ. निधी सुथार
शोध पर्यवेक्षक (गृह विज्ञान)
टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16693916

IMPACT FACTOR

5.924

सारांश

जंक फूड आधुनिक जीवन शैली की पहचान है। वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति जंक फूड को एक फैशन की तरह लेता है। जंक फूड खाना एक स्टाइल का प्रतीक माना जाता है। उसमें एक ऐसा स्वाद है जो व्यक्ति को बार–बार खाने के लिए लालायित और आकर्षित करता है। यह दिखावे की प्रवृत्ति से भी प्रभावित है परंतु जंक फूड में पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, जो शरीर में विभिन्न रोगों को जन्म देती है। लेकिन आज के दौर में जंक फूड को अपनाना जितना ही आसान है, उसे छोड़ना उतना ही कठिन प्रतीत होता है। यह किशोर और किशोरियों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचा रहा है जो भविष्य के लिए खतरे की संभावनाओं को प्रकट करता है। पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा, नूडल्स, पेस्ट्री बहुत ही आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति इन्हें कई बार इच्छा से तो कई बार मजबूरी में खाता है। लेकिन यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। वर्तमान में विशेषकर किशोर और युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में है जिन्हें मुक्त करना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए पोषक तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर ही अनेक क्षमताओं को जन्म देता है तथा भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह विकास की बहुत सी संभावनाओं को समाप्त कर देगा।

मुख्य शब्द– स्वास्थ्य, पोषक तत्व, रोग, पाचन तंत्र, त्वचा, मानसिक स्वास्थ्य।

प्रस्तावना

जंक फूड न केवल भारत में, बल्कि विश्व में प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ बन गया है। इसके लिए युवा वर्ग सबसे अधिक लालायित रहता है। यही प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ विश्व के लिए एक समस्या भी बन चुका है। आज का समाज तकनीक, सुविधा और त्वरित परिणामों से युक्त है। लोगों के पास समय की बहुत कमी है और जीवनशैली अत्यंत व्यस्त होती जा रही है। ऐसे में त्वरित भूख मिटाने और स्वादिष्ठ खाने के लिए लोग जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्वाद में लाजवाब है पर स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी – यही है जंक फूड की असली पहचान। यह आधुनिक जीवनशैली का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो बाजार, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस की कैंटीन में सरलता से उपलब्ध होता है और किसी विशेष आयोजन पर भी इसे ही परोसा जाता है। यह धीरे–धीरे हमारे शरीर, मन और समाज को खोखला कर ही रहा है, साथ ही पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद को भी विलुप्त करता जा रहा है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

स्वास्थ्य–

स्वास्थ्य शब्द अंग्रेजी भाषा के ऐंग्लो– सेक्सन शब्द से निर्मित है। जिसका उपयोग Health 'स्वास्थ्य की दशा' (Condition of being 'Hal') के लिए किया था। स्वास्थ्य का संबंध जीवन के सम्पूर्ण विकास की सीमा है। स्वास्थ्य को अंग्रेजी में हेल्थ कहते हैं। हेल्थ का अर्थ है–प्रसन्नचित मनुष्य का वास्तविक और सर्वश्रेष्ठ धन उसका स्वास्थ्य है। इसलिए कहा भी गया है–Health is Wealth, अतः स्वस्थ्य रहना ही प्राणी के लिए स्वयं के साथ–साथ सामाजिक दृष्टि से भी आवश्यक है मनुष्य के प्रत्येक अंग हर समय किसी कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर जितना अच्छा होगा उसके शारीरिक अंग उतनी ही क्षमता और तत्परता से कार्य करेंगे।

कलिन के शब्दो में– "स्वास्थ्य वह सम्पत्ति है जिसे मानव संसार के सभी सुखों को भोगते हुए प्रसन्न रहता है।"

जंक फूड–

जंक फूड वह भोजन है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम और वसा, नमक, शक्कर तथा कृत्रिम रसायनों की मात्रा अत्यधिक होती है। बहुत ही आकर्षक व खूबसूरत दिखने वाला यह भोजन देखते ही मुहँ में लार लेकर आता है। यह बाजार में विभिन्न स्वाद, रंग और रूपों में उपलब्ध है। जैसे– बर्गर, पिज्ज़ा, समोसे, मोमोज़, चिप्स, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, डोनट, फ्रेंच फ्राइज़, नूडल्स, चाऊमिन, इंस्टेंट फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, कुकीज़, कैंडी आदि।

ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट और आकर्षक तो होते ही हैं लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक सिद्ध होते हैं। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी ये प्रभाव डालते हैं।

मैकडोनल्डस के अनुसार– "फास्ट फूड वह फास्ट सर्विस है। जो बगैर किसी वेटर की सहायता के आपके मांग करने पर आपका स्वादिष्ट व पंसदीदा फूड आपके पास पहुँच जायें।"

जंक फूड : एक मीठा ज़हर होता है इससे निम्न समस्याएँ आती है–

1. पोषण की कमी

जंक फूड में फाइबर, विटामिन, प्रोटीन और खनिज तत्वों की कमी होती है। ऐसे भोजन से शरीर को कोई आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलता, जिससे कमजोरी, थकान और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है।

2 मोटापा

जंक फूड और मोटापे का गहरा संबंध है। जंक फूड में ट्रांस फैट्स, अधिक कैलोरी और चीनी होती है जो शरीर में चर्बी जमा कर मोटापा बढ़ाती है। यह मोटापा आगे चलकर मधुमेह, हृदय रोग और थायरॉइड जैसी बीमारियों का कारण बनता है।

3. हृदय संबंधी रोग

जंक फूड खाने से शरीर के अंदर बहुत सारी वसा जमा हो जाती है जिसकी वजह से हृदय रोग जैसी संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। अधिक नमक और वसा से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल असंतुलित होता है और हृदय पर दबाव पड़ता है। 20 से 40 की उम्र में ही हार्ट अटैक के मामले बढ़ने का बड़ा कारण यही है।

4. मधुमेह और उच्च रक्तचाप

जंक फूड को बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने वाला व्यक्ति यदि व्यायाम नहीं करता है तो उसके शरीर में विभिन्न रोगों का आमंत्रण हो जाता है। प्रोसेस्ड शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स का अत्यधिक सेवन इंसुलिन की मात्रा को असंतुलित करता है जिससे डायबिटीज़ हो जाती है।

5. पाचन तंत्र पर असर

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में फाइबर का होना बहुत आवश्यक है। जंक फूड में फाइबर का अभाव होता है। इसलिए पाचन तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जंक फूड में फाइबर नहीं होता, जिससे कब्ज, अपच और गैस की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पेट की आँतों की कार्यक्षमता भी धीरे–धीरे कमजोर हो जाती है। जो आगे चलकर नहीं समस्याओं को जन्म देता है।

6. त्वचा और बालों की समस्याएं

पोषक तत्वों की कमी तथा आवश्यक विटामिन की कमी के कारण शरीर के अंदर बहुत सारे अंगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। जंक फूड के कारण मुंहासे, बाल झड़ना, त्वचा का रूखापन और दाग–धब्बे आम हो जाते हैं। पोषक तत्वों की कमी त्वचा की चमक छीन लेती है। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ही चेहरे पर चमक तथा शरीर में ताकत और क्षमताओं को लेकर आता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

जंक फूड खाने का प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है और शरीर में शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। यदि दोनों ही प्रकार के स्वास्थ्य किसी प्रकार की हानि या नुकसान को उठाते हैं तो व्यक्ति को इसे जीवन भर भुगतना पड़ता है। जंक फूड का असर केवल शरीर पर ही नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि नियमित रूप से जंक फूड खाने वाले लोग अधिक चिड़चिड़े, उदास और तनावग्रस्त रहते हैं। इनके

निम्न कारण हैं–

* न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन

* ब्रेन फंक्शन में बाधा

* एकाग्रता में कमी

* नींद की गुणवत्ता में गिरावट

* गैस की समस्या

* घबराहट

* थकान आदि

उपरोक्त समस्याएं शरीर के संचालन को प्रभावित करती हैं तथा बच्चों तथा युवाओं में यह ध्यान भंग, हाइपरएक्टिविटी और पढ़ाई में रुचि की कमी का कारण बन सकती है। बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। यदि वे ही कमजोर पड़ जाएंगे तो देश को विभिन्न प्रकार के नुकसान उतने पड़ेंगे। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) विश्व में स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है तथा समय–समय पर सही सूचना और निर्देश भी देता है।

बच्चों और किशोरों पर प्रभाव

बच्चों की आदतें जल्दी बनती हैं और जीवनभर बनी रहती हैं। बच्चा कैसा भोजन खाता है तथा कैसा भोजन खाना चाहता है। इसका प्रभाव उसके चारों के वातावरण और माता–पिता के व्यवहार से पड़ता है। उसे घर में जैसा भोजन दिया जाएगा। वह उसी प्रकार के भोजन को करने का आदी हो जायेगा। यदि बचपन में ही जंक फूड खाने की लत लग जाए, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो सकता है जैसे–

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

* कद–काठी कमजोर होना

* दाँतों की समस्याएं

* पढ़ाई में ध्यान न लगना

* लीवर और किडनी पर असर

* बाल्यावस्था में ही मोटापा और हृदय रोग का खतरा

* अस्थमा का खतरा

* थकान

* चिड़चिड़ापन आदि समस्याएं उसे घेर लेती हैं।

आज के स्कूल–कॉलेज में मिलने वाले जंक फूड और सोशल मीडिया पर प्रचारित विज्ञापन बच्चों की आदतों को और बिगाड़ रहे हैं। वे उन्हें जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करते हैं और धीरे–धीरे उन्हें उस स्वाद का आदि बना देते हैं, जिसे वह बार–बार खाने के लिए ललायित रहते हैं क्योंकि यह सरलता से तथा बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं।

समाज पर प्रभाव

जंक फूड केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ता, यह समाज के समग्र स्वास्थ्य पर असर डालता है–

* अस्पतालों में बीमारियों की संख्या बढ़ती है।

* स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बढ़ता है।

* काम करने की क्षमता कम होती है।

* युवाओं में समय से पहले थकान और रोग हो जाते हें।

* भारत जैसे देश की कार्यशक्ति कमजोर हो रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार भारत में असंक्रमणीय रोगों से मरने वालों की बड़ी संख्या का एक मुख्य कारण अनियमित और असंतुलित भोजन है, जिसमें जंक फूड का बड़ा योगदान है। व्यक्ति इतनी जल्दबाजी और भागदौड़ में रहता है या उसके पास में पैसों की कमी होती है या वह भोजन का वितरण करना चाहता है तो इन सभी स्थितियों के अंदर जंक फूड एक सरल साधन है जो सरलता से उपलब्ध हो जाता है और जिसे बांटना, खाना हर तरह से सरल समझा जाता है।

आर्थिक दृष्टिकोण से हानि–

1. दूरगामी खर्च

जंक फूड बहुत आसानी से कहीं भी उपलब्ध हो जाता है तथा इसको बनाना भी बहुत सरल होता है और इसे सस्ते में भी खरीदा जा सकता है। शुरुआत में यह स्वादिष्ट और सस्ता लगता है लेकिन दीर्घकाल में इलाज में लाखों रुपये खर्च होते हैं– डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज अत्यंत महंगे हैं।

2. घरेलू बजट पर असर

स्वादिष्ट खाने का लालच भोजन पर बहुत अधिक व्यय का कारण बनता है। परिवारों का एक बड़ा हिस्सा स्नैक्स और फास्ट फूड पर खर्च होने लगा है, जो घर के पोषण और ज़रूरी चीजों पर खर्च को कम कर देता है।

3. स्थानीय परंपरागत खाद्य उद्योग को नुकसान

जंक फूड की वजह से घर की बनी चीजें, स्थानीय व्यंजन, अनाज, फल–सब्जियां आदि का उपभोग घटता जा रहा है, जिससे किसानों और घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है। जबकि विदेशों की बड़ी–बड़ी कंपनियां बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं।

समाधान और सुझाव

1. जागरूकता फैलाना

परिवार के बाद शिक्षक ही ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करता है, इसलिए यह एक शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह बच्चे को स्वस्थ भोजन, पौष्टिक तत्वों के बारे में बताएं तथा जंक फूड से होने वाले नुकसानों के बारे में चेतना जागृत करें। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में पोषण संबंधित शिक्षा दी जाए। टीवी और सोशल मीडिया पर स्वास्थ्यवर्धक भोजन का प्रचार किया जाना चाहिए ।

2. परिवार की भूमिका

भोजन के संदर्भ में परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में जो भोजन बनाया और खिलाया जाता है, बच्चे को उसी प्रकार के भोजन को खाने की आदत हो जाती है। इसीलिए माता–पिता और परिवार के बड़े सदस्यों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन का निर्माण करें। घरों में बच्चों को संतुलित भोजन की आदत डलवाएं। बच्चों को खाना बनाना सिखाएं ताकि वे खाने के महत्व को समझें। अपनी मेहनत से बनाए हुए खाने को वो खाना भी पसंद करते हैं।

3. स्कूल में प्रतिबंध

स्कूल कैंटीन में विभिन्न प्रकार के जंक फूड को बेचा जाता है। स्कूल प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा इस प्रकार के हानिकारक खाद्य पदार्थों के बेचने पर रोक लगानी चाहिए। उसके स्थान पर पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूल कैंटीन में जंक फूड की बिक्री और प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही इसकी जगह फल, अंकुरित अनाज, मिल्क शेक, छाछ, पोहा, उपमा आदि को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए ।

4. सरकारी नियंत्रण

सरकार को पोषक तत्वों और भोजन के संबंध में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इसके लिए उन्हें विज्ञापन और नुक्कड़ नाटकों का सहारा लेना चाहिए। जंक फूड पर टैक्स बढ़ाया जाए, इसके विज्ञापनों को नियंत्रित किया जाए और इनके लेबल पर चेतावनी लिखना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसे– तम्बाकू उत्पादों पर होता है।

5. स्वस्थ विकल्प अपनाएं

बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान माता ही रख सकती है। अतः माता को पौष्टिक भोजन बच्चों को सुबह शाम और रात के खाने में उपलब्ध करवाना चाहिए। जंक फूड की जगह घर में बने हेल्दी स्नैक्स जैसे– मूंग दाल चिल्ला, सब्ज़ी परांठा, स्प्राउट्स, मखाने, छाछ, फल, सूखे मेवे आदि खिलाएं। भोजन के साथ–साथ बच्चों और युवाओं को व्यायाम पर भी ध्यान देना चाहिए तथा विभिन्न खेल जैसे– दौड़, खो–खो, फुटबॉल, वालीबॉल खेलने चाहिए।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

निष्कर्ष

भोजन जीवन जीने का आधार है, इसीलिए व्यक्ति जीने के लिए भोजन को ग्रहण करता है, लेकिन यदि व्यक्ति भोजन के लिए ही जीना प्रारंभ कर दे तो व्यक्ति, स्वास्थ्य और परिवार के लिए समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में भोजन प्रतिष्ठा का सूचक भी है। प्रतिष्ठा की इस दौड़ में पारंपरिक भोजन पीछे गया और जंक फूड ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। जंक फूड एक ऐसा स्वाद और आकर्षण है जिसमें विश्व भर के न केवल बच्चे बल्कि युवा और बुजुर्ग भी गिरफ्त में हैं। यह भोजन बीमारों की संख्या में वृद्धि कर रहा है और स्वस्थ मनुष्यों की संख्या में कमी कर रहा है। पोषण युक्त भोजन, पूर्ण नींद और व्यायाम से व्यक्ति स्वयं को स्वस्थ बना सकता है। लेकिन जंक फूड खाने के बाद व्यक्ति में आलस, थकान और मोटापा आता है और वह व्यायाम और पोषण युक्त भोजन से दूर होने लगता है। जंक फूड एक ऐसा मीठा ज़हर है जो स्वाद की लालसा में हमें बीमारियों के गर्त में धकेल रहा है। यह केवल स्वास्थ्य ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों, समाज, देश और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। यदि समय रहते मनुष्य सचेत नहीं हुए, तो इसका दुष्परिणाम भयावह हो सकता है। स्वास्थ्य ही धन है– यह कहावत आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई है। हमें अपने भोजन की थाली को फिर से पारंपरिक, पौष्टिक और प्राकृतिक बनाना होगा। फिर से वही परंपराओं को लाना होगा। घर में एक साथ बैठकर भोजन करना, घर का बना भोजन करना, जमीन पर बैठकर भोजन करना, ऐसी बहुत सारी अच्छी आदतों को फिर से विकसित करना होगा। तभी हम एक स्वस्थ, सशक्त और दीर्घायु जीवन की ओर बढ़ पाएंगे।

संदर्भ सूची

1. चक्रवर्ती, सिद्धार्थ (2022) : भोजन के पोषक तत्व, ग्रीन लीफ पब्लिकेशन, वाराणसी – 221001
2. हाल्ज एबोलिनो, फेन्डराइक एवं हरमसेल रोबिन (1993) : किशोरावस्था में छात्रों का मानसिक विकाम, रावत पब्लिकेशन, जयपुर,
3. जिंदल (2023) : पोषण एवं स्वास्थ्य : शाकाहारी मार्ग, बी. जैन पब्लिशर्स, दिल्ली
4. शुक्ला , डॉ. अतुल (2021) : खेल, पोषण और स्वास्थ्य, खेल साहित्य केन्द्र, दरियागंज, नई दिल्ली
5. पाण्डेय, श्रीमती सुनीता (2007) : बालक–बालिकाओं में पोषण की कमी, जागृति प्रकाशन, 2001
6. पवार, विवेक शानू एवं मोरे, डॉ. राहुल (2018) : स्वास्थ्य शिक्षा और खेल पोषण, खेल साहित्य केन्द्र, दरियागंज, नई दिल्ली
7. कौशिक, डॉ. सज्जन एवं कुमार पवन (2023) : स्वास्थ्य शिक्षा और खेल पोषण , फ्रेंड्स पब्लिकेशन (भारत)
8. मुखर्जी, नमीता (1984) : बालकों में पोषण का अभाव, स्मार्ट पब्लिकेशन हाउस, जहाँगीरपूरी, नई दिल्ली,
9. रणमाल, डॉ. पांडुरंग श्री रंग (2016) : खेल पोषण तथा भार प्रबन्धन, खेल साहित्य केन्द्र, दरियागंज, नई दिल्ली
10. सिंह, डॉ. भूपेन्द्र (2021) : शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्य शिक्षा, फ्रैण्ड्स पब्लिकेशन (भारत)
11. कपूर, स्मिथ (1988) : बालकों में स्कूली शिक्षा का अभाव, मेहता आर्टस पब्लिकेशन।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

GREEN BANKING AWARENESS AND CUSTOMER ADOPTION PATTERNS : INSIGHTS FROM RAJASTHAN'S BANKING SECTOR

Veenus Mahipal
Research Scholar (Commerce)
Singhania University, Pacheri Bari, Jhunjhunu (Raj.)

Dr. Anil Tiwari
Research Supervisor
Assistant Professor
Department of Commerce and Management

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16694231

IMPACT FACTOR 5.924

ABSTRACT

The increasing environmental concerns and the global push toward sustainable development have prompted the banking industry to adopt eco-friendly practices under the umbrella of "green banking." This research paper investigates the level of awareness and adoption patterns of green banking initiatives among customers in the banking sector of Rajasthan. The study explores the extent to which customers are informed about green banking products and services, such as paperless transactions, online banking, green loans, and energy-efficient branches, and examines their willingness and behavioral trends in adopting these services.

A mixed-method approach has been employed, combining quantitative surveys from a sample of 500 customers across public and private sector banks in key cities of Rajasthan, including Jaipur, Udaipur, Jodhpur, and Kota, along with qualitative interviews of bank officials. The findings reveal a moderate level of awareness among customers, with higher awareness in urban areas and among younger, tech-savvy users. However, the actual adoption rate of green banking practices remains relatively low due to factors such as lack of information, perceived complexity, and limited promotional efforts by banks.

The study highlights the gap between awareness and adoption and identifies key drivers and barriers influencing customer behavior. It also provides recommendations for banks to design targeted awareness campaigns, invest in user-friendly digital platforms, and integrate environmental education into customer engagement strategies. The insights from this research contribute to policy formulation and the development of more sustainable and inclusive green banking frameworks in Rajasthan and beyond.

Key words: Green Banking, Customer Awareness, Sustainable Finance, Banking Sector, Environmental Sustainability, Digital Banking, Customer Adoption Patterns, Public and Private Sector Banks, Rajasthan, Eco-Friendly Banking Practices.

INTRODUCTION

In recent years, the global financial sector has witnessed a significant transformation with the emergence of environmentally responsible banking practices, commonly referred to as green banking. As environmental degradation and climate change have become pressing global issues, the role of financial institutions in promoting sustainable development has gained substantial importance. Green banking refers to initiatives undertaken by banks to promote eco-friendly practices, reduce their carbon footprint, and support sustainable economic growth through green products and services such as paperless banking, energy-efficient infrastructure, online banking, green loans, and support for environmentally responsible projects.

India, being a rapidly growing economy with a diverse banking sector, has embraced the concept of green banking through both regulatory encouragement and voluntary adoption. Institutions like the Reserve Bank of India (RBI) and Indian Banks' Association (IBA) have played key roles in promoting sustainable finance. However, the success of such initiatives largely depends on customer awareness, acceptance, and usage patterns. Without sufficient knowledge and motivation among customers, green banking may remain underutilized, especially in semi-urban and rural regions.

Rajasthan, as one of India's largest and most diverse states in terms of geography, demography, and economic activity, presents a unique context to study the awareness and adoption of green banking. With the presence of both public and private sector banks, and a mix of urban and rural customers, Rajasthan offers a representative landscape to analyze how customers perceive and adopt eco-friendly banking services.

This research aims to evaluate the level of awareness among customers regarding green banking initiatives and to examine their behavioral patterns in adopting such services. The study investigates differences in awareness and adoption across demographic groups, analyzes the role

of banks in promoting green initiatives, and identifies key factors that encourage or hinder the adoption of green banking in Rajasthan. The findings of this study are expected to provide valuable insights to banks, policymakers, and environmental advocates in designing more effective strategies for the promotion and implementation of green banking practices.

REVIEW LITERATURE

Jeucken (2001) have defined green banking as an initiative by financial institutions to consider environmental and social factors in their business operations. The World Bank and UNEP-FI (United Nations Environment Programme – Finance Initiative) have also emphasized the role of financial institutions in driving green growth and sustainable development. Studies from developed countries highlight that banks in Europe and North America have proactively integrated green banking practices into their lending portfolios and operations, often motivated by stricter environmental regulations and a socially responsible consumer base.

According to Indian Banks' Association (IBA, 2014), green banking aims to make banking processes, services, and customer habits more environmentally sustainable. Singh and Singh (2012) conducted a study revealing that many Indian banks have started offering green products such as green loans, e-statements, mobile banking, and online fund transfers to reduce paper usage and carbon emissions. However, the study also indicated that the adoption of green practices among banks remained limited to Tier-1 cities.

Kumar and Shekhar (2015) analyzed green banking practices in public and private banks in India and found that while private banks were more aggressive in adopting green initiatives, public banks lagged behind due to operational constraints and limited customer awareness. They emphasized the need for proper training of staff and public outreach to popularize green banking.

Jain and Jain (2017) studied customer perception of green banking in urban India and found that while most customers were aware of online banking and e-statements, they lacked knowledge about green loans or sustainable investment options. The study showed that younger customers and those with higher education levels were more inclined toward green banking services.

Nandini (2019) conducted a survey across rural and urban banks in South India and reported that customer adoption was influenced by the ease of use, perceived benefits, and promotional

strategies by banks. The study highlighted a significant awareness-adoption gap and called for more proactive communication strategies by banks.

Sharma and Meena (2020) conducted a study in Jaipur and Jodhpur and found that while customers were using digital banking services, they did not associate them with environmental benefits. The study identified a lack of promotional efforts and insufficient bank staff training as major barriers.

Rathore (2021) noted that private banks in Rajasthan, especially in cities like Jaipur and Udaipur, were more successful in creating awareness through digital campaigns and customer engagement programs. However, in rural areas, public sector banks had greater customer outreach but failed to promote green banking effectively due to technological and infrastructural limitations.

RESEARCH METHODOLOGY

The present research on Green Banking Awareness and Customer Adoption Patterns: Insights from Rajasthan Banking Sector adopts a mixed-method approach, combining both quantitative and qualitative techniques to provide a comprehensive understanding of the subject. The study is descriptive in nature, aimed at assessing the current level of awareness among banking customers and analyzing their behavioral patterns regarding the adoption of green banking services. The research was carried out across five major cities of Rajasthan—Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Kota, and Ajmer—chosen for their diverse economic activities and representation of both public and private banking clientele.

The sampling method used was stratified random sampling, allowing equal representation of customers from public and private sector banks. A total of 500 respondents participated in the survey, equally distributed between public banks like SBI, PNB, and Bank of Baroda, and private banks like HDFC, ICICI, and Axis Bank. To enrich the findings, 10 in-depth interviews were conducted with branch managers and officers responsible for green banking initiatives in selected banks. Primary data was collected using a structured questionnaire comprising closed-ended questions and Likert-scale items designed to capture customer awareness, usage frequency, satisfaction, and perceived barriers to green banking. The interviews provided qualitative insights into institutional strategies and operational challenges.

Secondary data sources included official reports from the Reserve Bank of India (RBI), Indian Banks' Association (IBA), sustainability disclosures of selected banks, and peer-reviewed journal

articles on green banking. Data analysis was conducted using SPSS software. Descriptive statistics such as frequencies, means, and percentages were used to summarize responses, while chi-square tests and cross-tabulations were employed to analyze relationships between variables like age, gender, and bank type. Qualitative data from interviews were analyzed thematically to identify recurring patterns, managerial perspectives, and suggestions for improvement.

Ethical considerations were strictly adhered to throughout the research process. Participation was voluntary, informed consent was obtained, and confidentiality of responses was maintained. The methodology thus ensures reliability, validity, and ethical integrity in studying green banking awareness and adoption among customers in Rajasthan.

GREEN BANKING INITIATIVES IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR BANKS

In India, both public and private sector banks have recognized the importance of integrating environmental sustainability into their operations and services. Green banking initiatives aim to reduce the carbon footprint of banking activities, encourage environmentally responsible behavior among customers, and support green financing projects. While the core principles of green banking remain the same across the sector, the approach and intensity of implementation often differ between public and private banks.

Public Sector Banks

Public sector banks (PSBs), such as State Bank of India (SBI), Punjab National Bank (PNB), and Bank of Baroda, have initiated several eco-friendly practices in recent years. These include the promotion of digital banking to reduce paper usage, installation of solar-powered ATMs, green home loans for energy-efficient housing, and e-statements instead of printed passbooks. SBI has been a frontrunner among PSBs, introducing the Green Channel Counter to encourage paperless transactions and launching the Green Home Loan scheme that offers incentives for buying environmentally sustainable homes.

Moreover, PSBs have adopted Core Banking Solutions (CBS) and mobile applications to reduce branch-based transactions, thereby decreasing electricity and fuel consumption. These banks also participate in government and regulatory initiatives related to green finance, including funding renewable energy projects, afforestation programs, and water conservation initiatives. However, the implementation speed and customer engagement in green practices are often slower in public

banks due to bureaucratic procedures, infrastructure limitations, and lower digital literacy among rural customers.

Private Sector Banks

Private banks such as HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, and Yes Bank have been more proactive and aggressive in implementing green banking practices. These banks have not only adopted internal environmental policies but also promote sustainable finance as a strategic priority. For instance, Yes Bank was one of the first Indian banks to publish a sustainability report in line with the Global Reporting Initiative (GRI) and actively fund renewable energy projects, green infrastructure, and climate-related innovations.

Private sector banks have also invested heavily in digital infrastructure to reduce dependency on physical branches. Initiatives such as e-wallets, mobile banking, net banking, and green fixed deposits are commonly promoted through digital marketing campaigns. Axis Bank, for example, has launched Green Banking services that reward customers for using digital channels, while HDFC Bank has supported environmental NGOs and awareness campaigns under its CSR initiatives.

Additionally, private banks often collaborate with international financial institutions for climate finance and adopt international sustainability frameworks such as the Equator Principles and UN Sustainable Development Goals (SDGs). Their operational flexibility, technological edge, and competitive environment allow them to implement green banking innovations more swiftly compared to public banks.

Comparative Insights

While both public and private sector banks contribute to green banking, private banks generally lead in terms of innovation, speed, and visibility of green initiatives. Public banks, on the other hand, have a wider reach, especially in rural and semi-urban areas, which gives them a unique advantage in spreading awareness and promoting green practices at the grassroots level. A collaborative approach, leveraging the strengths of both sectors, is essential to accelerate the adoption of green banking across the Indian banking ecosystem.

In conclusion, green banking in India is gaining momentum, but its success depends on a balanced integration of policy support, institutional commitment, technological investment, and customer awareness—elements that both public and private sector banks must actively pursue.

CUSTOMER AWARENESS AND PERCEPTION

Customer awareness and perception play a pivotal role in determining the success of green banking initiatives. While banks can introduce eco-friendly practices and promote sustainable products, the actual impact depends on how well these initiatives are understood, accepted, and utilized by customers. In the context of Rajasthan, a state with both urban and rural populations, varying literacy levels, and socio-economic diversity, customer awareness of green banking services shows a mixed pattern.

The study reveals that customer awareness regarding green banking is moderate overall but unevenly distributed across demographic segments. Urban customers, especially younger individuals (aged 18–35), and those with higher education levels, demonstrate significantly more awareness about green banking services such as mobile banking, internet banking, e-statements, and green home loans. Many of these customers associate such services with convenience, speed, and digital literacy rather than environmental sustainability. For example, users often adopt e-statements or mobile banking primarily to avoid visiting branches rather than to reduce paper consumption or carbon emissions.

On the other hand, in semi-urban and rural areas of Rajasthan, awareness levels are considerably lower. Many customers are not familiar with the term "green banking" and are unaware of its environmental benefits. They often consider traditional banking (such as using passbooks, physical forms, and cheque books) as more reliable. Limited access to digital infrastructure, low digital literacy, and language barriers further restrict the spread of green banking practices in these regions.

The perception of green banking is also influenced by trust, usability, and perceived risk. Customers who are digitally active and environmentally conscious view green banking positively and believe that it contributes to both personal convenience and ecological well-being. However, a significant number of customers, particularly the elderly and those from non-urban backgrounds, perceive green banking as complex, impersonal, and insecure due to concerns over cyber fraud and technical failures.

Interestingly, the study found that awareness campaigns by private banks, including app-based tutorials, SMS alerts, and digital marketing, were more effective in shaping positive perceptions among customers compared to public banks, which rely more on in-branch communication. Many public sector customers reported that they were unaware of green banking services until prompted during this survey, indicating a lack of proactive promotion.

In conclusion, customer awareness and perception of green banking in Rajasthan are shaped by demographic factors, digital exposure, bank communication strategies, and personal attitudes toward environmental responsibility. Bridging the awareness-adoption gap will require targeted outreach, multilingual promotional efforts, and simplified digital tools that cater to diverse customer groups. Only by aligning customer perception with the environmental goals of green banking can banks fully leverage the potential of sustainable finance in the region.

ADOPTION PATTERNS AND BEHAVIOR

Understanding customer adoption patterns and behavior is essential to evaluate the real-world impact of green banking initiatives. While awareness forms the foundation, actual usage—or adoption—of green banking services reflects the effectiveness of these initiatives in driving environmentally sustainable financial behavior. The study conducted across various districts in Rajasthan reveals important trends and insights into how customers interact with green banking services, what influences their adoption, and what barriers they face.

The analysis indicates that green banking adoption is growing, but it is more convenience-driven than environment-driven. Customers in urban areas, particularly those between the ages of 20–40, show a higher tendency to adopt digital banking services such as mobile banking apps, internet banking, UPI payments, e-wallets, and e-statements. However, most of them perceive these services as tools for saving time, reducing physical visits to the bank, and improving financial control—not as an effort toward environmental protection. Thus, while the adoption is high among this group, the environmental consciousness behind the usage is often incidental.

In contrast, customers in semi-urban and rural areas display lower adoption rates. Many continue to rely on traditional banking channels such as passbooks, cheques, cash deposits, and in-person transactions. Reasons include lack of digital literacy, fear of online fraud, irregular internet access, and mistrust in digital systems. Among these customers, the adoption of green banking practices is slow and often limited to SMS banking or ATM usage.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Another observation is that private sector bank customers are more likely to adopt green banking services than public sector bank customers. Private banks invest more in mobile apps, digital awareness campaigns, and seamless online interfaces, which encourage higher engagement. Public sector banks, while having broader reach in rural areas, often lack the digital infrastructure or customer education programs necessary for encouraging widespread adoption.

Behavioral analysis also shows that peer influence, educational background, and bank encouragement significantly impact adoption. Customers who were personally guided by bank staff or friends in using digital or green services were more likely to continue using them. Moreover, the presence of loyalty rewards or incentives (such as cashback for using e-statements or digital wallets) also motivated repeat usage.

* Despite these advances, several barriers hinder full-scale adoption. These include:
* Lack of awareness about the environmental benefits of green banking
* Poor technical support or app glitches
* Fear of online fraud or data privacy issues
* Language barriers in app usage
* Limited banking infrastructure in remote areas

In conclusion, adoption of green banking services in Rajasthan is influenced by a combination of demographic, technological, and institutional factors. While urban, younger, and digitally literate customers show higher adoption, rural and elderly populations lag due to infrastructural and perceptual barriers. To promote consistent and sustainable adoption behavior, banks must address these challenges through targeted digital inclusion programs, localized communication strategies, user-friendly platforms, and education that ties digital practices to environmental responsibility.

Data Analysis and Interpretation

To understand the trends in customer awareness and adoption of green banking services, data was collected from 500 respondents across five major cities of Rajasthan. The responses were categorized by age groups and location (urban vs. rural) to analyze demographic variations in green banking behavior.

Table – 1 Awareness and Adoption by Age Group

Age Group	Awareness (%)	Adoption (%)
18-25	75%	68%
26-35	82%	74%
36-45	65%	58%
46-60	48%	40%
60+	32%	25%

Interpretation:

The age group 26–35 showed the highest awareness (82%) and adoption (74%) of green banking services, indicating that young, working-age individuals are the most engaged demographic. This can be attributed to higher digital literacy, professional exposure, and familiarity with online platforms. The adoption rate steadily declines in higher age brackets, with only 25% of customers aged 60+ adopting green banking services. This highlights a clear digital divide and resistance to change among the older population.

Table – 2 : Urban vs. Rural Adoption Trends

Age Group	Urban Adoption (%)	Rural Adoption (%)
18-25	80%	60%
26-35	85%	65%
36-45	70%	55%
46-60	50%	45%
60+	35%	20%

Interpretation:

Urban customers consistently show higher adoption levels than their rural counterparts across all age groups. The urban-rural gap is most pronounced in the 26–35 and 60+ categories. While urban areas benefit from better infrastructure, internet access, and frequent exposure to digital campaigns, rural areas face constraints like lack of awareness, digital illiteracy, and poor connectivity. Only 20% of rural respondents aged 60+ adopted green banking, indicating that rural elderly are largely excluded from digital banking benefits.

General Observations and Patterns

* A positive correlation exists between age and digital comfort: younger users adopt green banking more readily.
* Public sector bank customers reported slower adoption compared to private sector customers due to less aggressive promotion and outdated digital platforms.
* Mobile banking and e-statements were the most widely used green services, while green loans and paperless onboarding were less known.
* Adoption is more convenience-driven than environmentally motivated—users prefer online banking for ease, not for sustainability.

Conclusions from Data Analysis

* Awareness does not always translate into adoption—some aware customers still hesitate to use green banking due to fear of fraud or technical challenges.
* Banks must focus on rural outreach, especially targeting older customers, to reduce the adoption gap.
* Personalized guidance, user-friendly apps, and multilingual customer education will be essential for improving adoption rates.
* Green banking adoption can be significantly boosted if customers are made more aware of its environmental benefits, not just convenience.

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

FINDINGS AND DISCUSSION

The study reveals that customer awareness regarding green banking practices in Rajasthan is moderate but unevenly distributed across age groups, regions, and types of banks. Awareness is notably higher among younger, urban customers aged 18–35, who are more digitally literate and engaged with online banking services. In contrast, awareness significantly declines among customers aged 46 and above, particularly in rural areas, where limited access to digital infrastructure, lack of exposure, and low technological familiarity remain key barriers.

One of the most significant findings is the presence of a clear gap between awareness and actual adoption. While a large number of customers were aware of services like e-statements, ATM usage, and internet banking, a smaller proportion regularly used these services with an environmentally conscious mindset. The primary motivation for adopting green banking practices was convenience and time-saving, rather than concern for environmental sustainability. This indicates that the concept of "green" in green banking remains abstract or misunderstood by a large portion of the customer base, especially in non-urban regions.

The study also highlights that private sector banks are more proactive in promoting green banking initiatives compared to public sector banks. Private banks have invested in modern digital platforms, run targeted awareness campaigns, and often link green practices with financial incentives. As a result, customers of private banks show higher engagement and a more favorable attitude toward green banking. Public sector banks, despite having a larger rural customer base and deeper reach, lag behind due to outdated digital systems, limited promotional efforts, and lack of personalized guidance for customers unfamiliar with digital platforms.

Furthermore, behavioral analysis suggests that demographic variables such as age, education level, and occupation significantly influence adoption patterns. Younger and professionally active individuals, particularly in urban areas, are more open to using mobile apps, online fund transfers, and opting for paperless communication. On the other hand, elderly users often express distrust in digital channels, fear of cyber fraud, and preference for physical documentation.

The findings also align with previous studies that point toward a growing reliance on digital banking tools in urban India, but a persistent awareness-adoption gap in semi-urban and rural regions. While some bank officials reported efforts to organize customer awareness programs and

"digital literacy" campaigns, their effectiveness remains limited due to language barriers, low turnout, and insufficient follow-up.

In conclusion, the study underlines that while green banking adoption is gradually increasing in Rajasthan, it is largely being driven by urban youth who associate it with convenience rather than environmental responsibility. There remains a pressing need to reframe green banking not just as a digital service but as a collective environmental responsibility. For this, banks must implement structured awareness campaigns in regional languages, simplify user interfaces, and offer hands-on assistance to first-time users, especially in rural areas. Only with such inclusive and targeted strategies can the full potential of green banking as a tool for environmental sustainability be realized.

CONCLUSION

The present study aimed to evaluate customer awareness and adoption behavior regarding green banking initiatives in the public and private banking sectors of Rajasthan. The findings clearly highlight a growing but uneven understanding of green banking among customers, with adoption patterns largely influenced by demographic factors such as age, location, education level, and digital literacy. While younger and urban customers have shown relatively high levels of awareness and adoption—primarily driven by convenience and digital familiarity—there remains a substantial gap in engagement among older populations and rural customers, who often lack access, guidance, or confidence in digital platforms.

Private sector banks have emerged as early adopters and effective promoters of green banking services, with strategic investments in digital infrastructure and customer-centric communication. In contrast, public sector banks, despite their deeper rural penetration, continue to lag in promoting eco-friendly practices due to limited innovation and outreach. The study also found that customer behavior is driven more by personal utility than environmental responsibility, suggesting a disconnect between the functional use of green services and their intended ecological purpose.

To address this, banks must adopt a dual approach: first, to strengthen digital literacy and accessibility across all customer segments—especially in rural areas—and second, to frame green banking within the larger context of environmental consciousness through targeted educational campaigns. Simplified interfaces, multilingual support, personalized assistance, and incentivized adoption schemes can further accelerate green banking engagement.

In conclusion, green banking in Rajasthan holds significant potential to contribute to both financial inclusion and environmental sustainability. However, its success will depend on bridging the awareness-adoption gap, fostering trust in digital systems, and aligning customer behavior with sustainable values. With coordinated efforts from banks, regulators, and civil society, green banking can evolve from a niche initiative to a mainstream financial and ecological movement.

REFERENCES

1. Awasthi, A., & Bedi, R. (2019). Green banking in India: A study of customer awareness and perception. International Journal of Management Studies, 6(1), 45–53.
2. Indian Banks' Association. (2014). IBA green banking initiatives. Retrieved from https://www.iba.org.in/green-banking
3. Jain, P., & Jain, R. (2017). Customer perception and adoption of green banking: An empirical study in India. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(10), 253–262.
4. Jeucken, M. (2001). Sustainable finance and banking: The financial sector and the future of the planet. Earthscan Publications.
5. Kumar, S., & Shekhar, R. (2015). Green banking in India: An overview. Global Journal for Research Analysis, 4(11), 154–156.
6. Nandini, V. (2019). Green banking awareness: A comparative study between rural and urban customers in South India. Journal of Commerce and Accounting Research, 8(3), 12–20.
7. Reserve Bank of India. (2021). Report on trend and progress of banking in India 2020–21. https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=20574
8. Rathore, M. (2021). Comparative study of green banking practices in private and public sector banks in Rajasthan. International Journal of Finance and Management, 13(2), 78–85.
9. Sharma, L., & Meena, R. (2020). A study of awareness of green banking initiatives in Rajasthan. Journal of Management Research and Analysis, 7(4), 127–133. https://doi.org/10.18231/j.jmra.2020.027

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का ऐतिहासिक उपदेयता

नितेश धनेलिया

विषय : इतिहास

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

ABSTRACT

मोहना के तोमर राजपूतों का संबन्ध मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान के राजपूतों से था। समय के अनुसार रिश्ते बदलते रहते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते है। ऐतिहासिक साक्ष्य विभिन्न प्रकार की राजपूतों की वंशावली की जानकारी देते हैं। देववर्मा की मृत्यु संभवतः 1375 ई. में हुई थी। मेजर जनरल कनिंघम ने 1375 ई. से वीरसिंहदेव का ऐसाह की गद्दी पर आसीन होना माना है।

1378 ई. के आस-पास वीरसिंहदेव ने अपनी गतिविधियाँ प्रारम्भ की थी। यद्यपि देववर्मा की जागीर की पुष्टि फिरोज तुगलक ने की थी, तथापि इस प्रदेश के राजपूतों के हृदय में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की प्रबल कामना कार्य कर रही थी और अवसर भी आ रहा था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 20 सितम्बर 1388 ई. को हो गई तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् तुगलक साम्राज्य भी डांवाडोल होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों में झगड़ा प्रारम्भ हो गया, फिरोज का पौत्र गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा।

मुख्यबिन्दु : ऐतिहासिक, साक्ष्य, वंशावली, जागीर, साम्राज्य

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16755012

IMPACT FACTOR

5.924

मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का ऐतिहासिक उपदेयता

मोहना के तोमर जागीरदारों के सम्बन्ध में विभिन्न इतिहासकारों के अलग- अलग मत है। मुसलमान और राजाओं ने हर जगह दिल्ली के प्रभुत्त अपने को मुक्त कर लिया। अधिकतर मोहना के तोमर जागीरदार तुगलक वंश के नजदीक थे परन्तु 16वीं शताब्दी के अन्त तक तोमरों का विस्तारीकरण होता रहा है। वीरसिंहदेव तोमर, तोमर शासकों के प्रमुख व शक्तिश्साली थे। कुछ इतिहासकारो तथा वृंदावनलाल वर्मा बहुत से ऐतिहासिक प्रामाण दिये जिनका सम्बन्ध ग्वालियर के तोमर, नरवर के तोमर एवं मोहना के तोमर जागीरदारों से है।

मध्यकाल में 1526 ई. में भारत में मुगल बादशाह बाबर ने मुगलवंशीय शासन की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की थी। बाबर का शासनकाल 1526-1530 ई., हुमायू का 1530-1556 ई., अकबर का 14 फरवरी 1556-1605 ई., जहांगीर का 1605-1627 ई.,

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

शाहजहां का 1628- 1658 ई., औरंगजेब का 1658-1707 ई. एवं उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में औरंगजेब के पुत्र बहादुरशाह प्रथम का 1707-27 फरवरी 1712 ई., जहांदारशाह का 1712-1713 ई., फर्रुखसियर का 1713-1719 §., रफी - उद दरजात ने 28 फरवरी से 4 जून 1719 ई., रफी - उदद्यौला ने 6 जून से 17 सितम्बर 1719 ई. तक, मुहम्मदशाह ने सितम्बर 1719 ई. से अप्रैल 1748 ई. तक अहमदशाह ने 1748-1754 ई., आलमगीर द्वितीय ने 1754- 59 ई. तक शासन किया। शाहआलम द्वितीय 1759-1806 ई. तक नाममात्र का शासक रहा क्योंकि वास्तविक सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में आ गई। 1858 ई. में अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह द्वितीय को रंगून से निर्वासित कर भारत में ब्रिटिश सरकार को वास्तविक शासक घोषित कर दिया गया।'

तोमर राजपूतों को तंवर नाम से संबोति किया जाता है। तंमर अधिकतर राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, हिमाचल एवं जम्मू कश्मीर में तंवर वंश के लोग अलग-अलग भागों में पाये जाते हैं। 736 ई. में दिल्ली राज्य के संस्थापक तंवर राजपूत जिन्होंने 1193 ई. तक दिल्ली राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित रखा था एवं 1394 ई. से 1523 ई. तक ग्वालियर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित रखने वाले तंवर राजपूतों के वंशज श्यामसिंह तोमर संभवतया 1577 ई. से 1615 ई. (संवत् 1634 से 1672) तक मोहना के जागीरदार रहे थे। श्यामसिंह के उपरांत मोहना के जागीरदार क्रमशः सरदार सिंह 1615-1636 ई. (संवत् 1672 से 1693), गजसिंह 1636-1660 ई. (संवत् 1693 से 1717), पृथ्वीसिंह 1660 से 1696 (संवत् 1717-1753), भौमसिंह 1696- 1749 ई. (संवत् 1753 से 1806), जगमोहन सिंह 1749-1750 ई. (संवत् 1806 से 1807), परीक्षित सिंह 1750 से 1778 ई. (संवत् 1807 से 1835), सीताराम सिंह 1778-1805 ई. (संवत् 1835 से 1862), पृथ्वीपाल 1805-1811 ई. (संवत् 1862 से 1868), वैरीशालसिंह 1811-1869 ई. (संवत् 1868 से 1926), भूपसिंह 1869 - 1902 ई. (संवत् 1926 से 1959), उमराव सिंह 1902-1904 ई. (संवत् 1959 से 1961), एवं सुल्तान सिंह 1904-1925 ई. (संवत् 1961 से 1982) रहे थे।

इधर वीरसिंहदेव वे उसके राजपूत संगठन ने शक्ति सम्पदा का संग्रह प्रारम्भ कर दिया वे स्वतंत्र होने के लिए तत्पर थे । अबूबक्र को हटाकर जब मुहम्मदशाह इटावा आया। वहां उसने वीरसिंह से भेंट कीं । "उस समय सुल्तान को राजपूतों के समर्थन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने वीरसिंह को खिल्ल दी और उसकी जागीर में वापस भेज दिया।"

मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले की तहसील घाटीगांव में मोहना ग्राम स्थित है। मोहना ग्राम आगरा मुंबई राष्ट्रीय मार्ग 3 पर ग्वालियर से दक्षिण पश्चिम में 57 कि.मी. की दूरी पर है। मोहना में 1577 ई. से 1924 या 25 ई. तक तोमर राजपूत जागीरदारों का प्रभाव स्थापित रहा था। तोमरों की उत्पत्ति सोमवंश (चन्द्रवंश) से मानी जाती है, जो इन्द्रप्रस्थ के पांडवों के वंशज थे । मोहना के तोमर जागीरदारों का मूल निवास स्थल म.प्र. के मुरैना जिले की अंबाह तहसील से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित 'ऐसा' नामक ग्राम है। ऐसा के तोमर राजपूतों ने सामंत राजा अथवा भूपति या जागीरदार के रूप में चंबल क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित किया था। चंबल क्षेत्र के इन सामंतों का उल्लेख पेहवा के शिलालेख' में प्राप्त होता है। तोमर जागीरदारों की तीन तालुका के अर्न्तगत 52 ग्राम (वावन), 84 ग्राम (चौरासी) एवं 120 ग्राम (वीसा सौ) मानी गई है।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

खड्गराय एक श्रेष्ठ वंशावली लेखक थे, उनके विचार श्रेष्ठ थे । खड्गराय की वंशावली ऐतिहासिक दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। 975 ई. के आसपास संभवतः दिल्ली के सम्राट के संकेत पर ही विट्ठलदेव ने अपने इलाके को संगठित किया । विट्ठलदेव ने अपने अधीन 120 ग्राम रखे और 'ऐसा' को अपनी राजधानी बनाया। विट्ठलदेव के पश्चात् रावतों (सामंतों) की इस शाखा की आठ पीढ़ियाँ रही इनकी वंशावली खड्गराय के अनुसार इस प्रकार से है बिट्ठलदेव (2) रूद्र (3) ग्यानचंद्र (4) ध्यानचंद्र (5) लोहंगदेव (6) शक्तिसिंह (7) मणिदेव (8) खाना (9) चन्द्रभानु आदि ।

736 ई. में अपना राज्य दिल्ली में स्थापित करने वाले तोमर शासकों में से चाहड़पाल देव तराइन के द्वितीय युद्ध में 1 मार्च 1192 ई. को मारा गया। चाहड़पाल देव का युवराज तेजपाल केवल 15 दिन के लिए दिल्ली पति बना। उसे भी 17 मार्च 1992 ई. में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हाथ पराजित होना पड़ा। वह तुर्कों के करद राजा रूप में कुछ समय तक राज्य करता रहा। सन् 1193 ई. में उससे दिल्ली छीन ली गई। उसने पुनः दिल्ली प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु सफल न हो सका और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका सिर काटकर दिल्ली में उसके राजप्रसाद पर टंगवा दिया। अब तेजपाल का पुत्र अचलब्रह्म और अजमेर के हरिराज ने दिल्ली प्राप्त करने का प्रयास किया परन्तु सन् 1194 ई. में दोनों पराजित हुए तत्पश्चात् अंचलब्रह्म तोमर रणक्षेत्र में पराजित होकर चंबल क्षेत्र की अपनी प्राचीन राजधानी 'ऐसा' आ गए। अचलब्रह्म के उपरांत वीरशाह, मदनपाल, भूपति, कुवंरसी, घाटमदेव, देवब्रह्म, वीरसिंह देव, 'ऐसा' के जागीरदार रहे। 3 वीरसिंह देव ने 4 जून 1394 ई. में ग्वालियर में तोमर राज्य स्थापित किया था। इस वंश के अंतिम शासक विक्रमादित्य तोमर का शासन संभवतया 1523 ई. तक स्थापित रहा था । विक्रमादित्य को इब्राहीम लोदी ने युद्ध में पराजित किया था। 21 अप्रैल 1526 ई. को विक्रमादित्य पानीपत के मैदान में इब्राहीम लोदी की ओर से करद सामंत के रूप में बाबर की सेना के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ मारा गया। मोहना के तोमर जागीरदारों का शासन करने का तरीका अन्य शासकों से अलग था। तोमर वंश के शासकों की नीतियाँ अन्य शासकों अलग था, वे सभी धर्मो का आदर करते थे। उन्होंने भाण्डेर, करैरा, नरवर, अमोला, पर शासन किया।

ग्वालियर किले को जिब्राल्टर की उपाधि से संबोधित किया गया। यूनेस्को ने ग्वालियर किले को इतिहास की दृष्टि से उसे ऐतिहासिक गढ़ माना है।

ग्वालियर के किले पर 11वीं शताब्दी से आजादी तक बहुत से लोगो ने शासन किया जिसमें तोमर वंश, खिल्जी वंश, मुगल अंग्रेज और मराठा ने शासन किया। ग्वालियर गढ़ पर मुगलों के पूर्व तोमरों का शासन था । तोमरों में राजा मानसिंह अधिक ताकतवर व शक्तिशाली थे परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे-धीरे तोमर शासक कमजोर पड़ते गये और उनके स्थान पर सल्तनत एवं मुगलों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, जिस कारण से तोमर वंश के शासकों की शक्ति क्षीण हो गई। ग्वालियर गढ़ पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो जाने के उपरांत विक्रमादित्य का राजकुमार रामसिंह तोमर मेवाड़ चला गया। रामसिंह तोमर ने 1558 ई. में कुछ सैनिकों के साथ ग्वालियर गढ़ पर आक्रमण कर अपने पूर्वजों के राज्य पर अधिकार करने का प्रयास किया परन्तु "किया खां' मुगल शासन की ओर से तंवर सेना को पराजित कर दिया । मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह (1572 से 1597 ई.) के शासनकाल में उनका मुगल बादशाह अकबर के साथ 18 जून 1576 ई. को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रामसिंह तोमर अपने तीनों पुत्र शालिवाहन, भवानी सिंह एवं प्रताप सिंह के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। टाड़ के अनुसार साढ़े तीन सौ तंवर वीरों ने संग्राम भूमि में बलिदान दिया था। हल्दीघाटी के युद्ध के उपरांत शालिवाहन

तोमर के दो राजकुमार श्यामसिंह और मित्रसेन ही जीवित बच सके थे। अकबर की विजय के पश्चात् श्यामसिंह और मित्रसेन मुगलों की सेना में आ गये थे। मुगल दरबार में इन्हें 'ग्वालियर के राजा' कहा जाता था।

1394 ई. के जनवरी या फरवरी माह में बादशाह का फरमान लेकर वीरसिंहदेव अपने दल-बल के साथ ग्वालियर गढ़ पर आए। उस समय ग्वालियर का अमीर (प्रशासक) अहमद बिल शेर खाँ का पुत्र या पौत्र अमीर था । वीरसिंहदेव ने उसे शाही फरमान दिखलाया और ग्वालियर गढ़ सौंपने को कहा । ग्वालियर गढ़ इल्लुतमिश ने 1232 ई. में जीता था। तब से लेकर 1394 ई. तक यह किला दिल्ली के बादशाहों के अधीन रहा। यहाँ पर बड़े-बड़े कैदियों को रखा जाता था। तुर्क सुल्तानों के इतिहास में यह पहली घटना थी जब तुकों द्वारा विजित गढ़ राजपूतों को सौंप दिया गया। इस बात पर प्रशासक को विश्वास नहीं हो रहा था, एक और वह सुल्तान के फरमान की अवहेलना भी नहीं कर सकता था, इसलिए टालमटोल करने लगा ।" वीरसिंहदेव ने उसके व्यवहार से क्रुद्ध होकर दिल्ली जाकर सुल्तान से सैन्य बल की सहायता लेने का निश्चय किया, इस पर उनके मंत्रियों ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया और कहा कि दिल्ली जाने से सम्भव है जो कुछ मिला है वह भी वापस न चला जाए।

मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबन्ध में इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं इनमें प्रमुख अबुल फजल है। तोमर राजपूतों के वंश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का विवरण जागाजी या पटिया के द्वारा समय-समय पर लिखा जाता रहा है। मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों के वंश लेखक देवीसिंह बड़वाजी (जागाजी या पटिया) पुत्र श्री उमराव सिंह बड़बाजी ग्राम तुंगा जिला- जयपुर, राजस्थान के द्वारा उनके पुरखों की हस्तलिखित वंशावली के आधार पर मोहना के तोमर राजपूतों की वंशावली प्राप्त हुई है। इस वंशावली के अनुसार 'राजा घाटमदेव' ने 'ऐसा' में राज्य किया। उनके वंश में वीसासौ (एक सौ बीस) ग्राम बसे । राजा घाटमदेव के वंश में शामराव हुए जो मोहना की गद्दी पर बैठे। शामराव ऐसा से करियारा, करियारा से मोहना आए और मोहना की जागीरदारी संभाली।

करियारा मोहना से लगभग 15-20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। मोहना की जागीरदारी प्राप्त होने से पूर्व शामराव का करियारा में निवास स्थान था। शामराव के पूर्वज घाटमदेव ऐसा के मूल निवासी और जमींदार थे। घाटमदेव के पौत्र वीरसिंह देव ने वि.स. 1439 (1382 ई.) में वीर सिंहावलोक नामक वैद्यक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में वीरसिंह देव ने घाटमदेव का नाम कमलसिंह लिखा है । इतिहासकार कनिंघम ने स्थानीय तोमर जागीरदार से एक अन्य वंशावली प्राप्त की थी, जिसमें घाटमदेव का नाम 'कुंवरपाल' अंकित है । गोपाचल आख्यान में घाटमदेव नाम उल्लिखित है। इन्हीं घाटमदेव के वंश में आगे चलकर शामराव हुए। हरिहर निवास द्विवेदी द्वारा किये गये तोमर वंश के गहन शोध अध्ययन के उपरांत ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के पुत्र रामसिंह के ज्येष्ठ पुत्र शालिवाहन के दो पुत्र जो हल्दीघाटी के युद्ध के उपरांत शेष बचे थे, उनका नाम श्यामसिंह और मित्रसेन बताया गया है। रामसिंह तोमर की 1576 ई. में हल्दीघाटी के युद्ध में मृत्यु हो जाने के उपरांत श्यामसिंह और मित्रसेन अकबर (1556-1605 ई.) के राज्यकाल में मुगलों की सेना में भर्ती हो गए थे। और अकबर इनके वीरत्व की सतत् सराहना करता रहता था। यहां इन्हें 'ग्वालियर के राजा' कहा जाता था । '

संदर्भ सूची

1. मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का इतिहास एपीग्राफी का इंडिका (भाग - 1) पृ. क्र.-242.

2. थापर, रोमिला मध्यकालीन भारत, पृ. क्र. - 26
3. खड्गराय कृत गोपाचल आख्यान, पृ. क्र. -84
4. कृष्णन, व. सु. ग्वालियर गजेटियर, पृ. क्र. -33
5. द्विवेदी, हरिहर निवास - दिल्ली के तोमर, पृ.क्र. 256, 257

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का राजनैतिक एवं ऐतिहासिक प्रासंगिकता

नितेश धनेलिया

विषय : इतिहास

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

Paper Rcevied date

05/07/2025

Paper date Publishing Date

10/07/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.16755242

IMPACT FACTOR

5.924

ABSTRACT

इतिहास में घटनाओं के प्रायः पुनरावृति देखी जाती है, इसका तात्पर्य यह नहीं है, कि इसमें कोई घटना होती ही नहीं, किन्तु असाधारण नई घटना भी भविष्य में फिर होने की आशा रखती है। मोहना के तोमर राजपूत विशेष रूप से सिंधिया परिवार से जुड़े हुए थे विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा तोमर राजपूतों की परम्पराएँ रीति रवाज और तौर तरीके उनके किस प्रकार के थे । तोमर जागीरदारों के सामाजिक रीति-रवाज, धार्मिक परम्पराएँ एवं सांस्कृतिक जीवन शैली अन्य राजपूतों से अलग थी। मोहना की गढ़ी से शोधार्थी ने जाके स्वयं साक्षात्कार लिया कि वर्तमान में तत्कालीन स्थितियों के सम्बंध में जानकारी लेने का प्रयास किया।

हमारे समाज में आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक वर्णव्यवस्था का विशेष महत्त्व है इसके अलावा वर्ण, वर्ग एवं जति ने समाज को विभिन्न भागों में बाँट रखा है। वैदिककाल से लेकर वर्तमान काल तक वर्ण व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन हुए है। वर्ण से तात्पर्य वृत्ति से है, किसी विशेष व्यवसाय के चुनने या वरण करने से है। समाज शास्त्र में वर्ण का अर्थ वर्ग से है, जो अपने चुने

हुए व्यवसाय में संलग्न है और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण समाज वर्गों अथवा समूहों से सर्वथा अलग होता है।

मुख्यबिन्दु : इतिहास, पुनरावृति, परम्पराएँ, रीति रवाज, व्यवस्था

आर्य वर्ण और दास वर्ण अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण व्यवस्था में रह गये। प्रारंभिक तीन वर्षों में आर्यों एवं चतुर्थ वर्ण में अनार्य अथवा दास को शूद्र वर्ण के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है। पालनकर्ता और

सत्य के अनुसार चलने वाला होना चाहिए। इन नियमों पर अत्याधिक जोर दिया गया है । क्षत्रिय शासक सदैव धर्म से डरते थे

" ऋतानानां निषेदतु साम्राज्याय सुक्रतु ।

धृतता क्षत्रिया क्षत्रमाशतु ।।" (1)

ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जो धर्म के विपीरत हो । मुगलकाल (1526-1761 ई.) में हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के बन्धन शिथिल होने लगे। हिन्दू निम्न जाति एवं वर्ग से संबंधित लोग इस्लाम के मिल्लत (भाईचारे) के सिद्धांत से प्रेरणा प्राप्त करके इस्लाम की

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

ओर आकर्षित होने लगे, जिसके फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में नवीन युग का आविर्भाव हुआ। इस सम समाज सामन्तवादी आधार पर संगठित था, जिसका प्रमुख बादशाह होता था । मुगलकालीन समाज दो भागों में विभाजित था:-

हमारा समाज विभिन्न प्रकार जाति, उपजाति एवं गोत्रों में बँटा है। जैसे हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं ईसाई है सभी को धर्म के आधार पर बाँट रखा है। हिन्दू प्रमुख रूप से अवतारवाद में विश्वास रखता है, जबकि मुस्लिम अवतारवाद नहीं मानते किन्तु दो भागों में बँटे है, शिया एवं सुन्नी, बौद्ध लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, इसके अलावा जैन तीर्थंकर को मानते है एवं ईसाई समुदाय प्रभु ईशु को मानते हैं। बौद्ध को मानने वाले दो भागों में विभाजित हैं हीनयान एवं महायान, जैन लोग श्वेताम्बर एवं दिगम्बर में विभाजित हैं तथा ईसाई समुदाय कैथोलिक एवं प्रोटोस्टंट में विभाजित हैं। मुस्लिम समाज में सर्वोच्च स्थान बादशाह का था। शाही परिवार और अभिजात वर्ग स्थित थे, जो राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर एकाधिकार जमाये हुए थे। बादशाह और अभिजात वर्ग के बाद तीसरा स्थान मध्यम वर्ग को प्राप्त था, जिसमें छोटे व्यापारी, लेखक, काजी और छोटे मनसबदार आदि सम्मिलित थे। इस वर्ग के लोगों के पास धन और बुद्धि दोनों थे। अतः कुछ अत्यन्त सम्पन्न लोगों को छोड़कर शेष का जीवन सरल था । चतुर्थ वर्ग में कारीगर, कृषक, सेवक, सिपाही और अत्यन्त छोटे दुकानदार और शिल्पी सम्मिलित थे। उनकी आर्थिक दशा अत्यन्त हीन थी। इनको बहुत कम वेतन मिलता था। सबसे दयनीय स्थिति दासों की थी। भारतीय मुसलमान छोटे-मोटे कार्यों के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे और विदेशी मुसलमानों की आय पर ही जीवन व्यतीत करने के लिये

बाध्य |

श्रीकृष्ण ने गीता में क्षत्रियों का निम्न प्रकार से उल्लेखस किया है, कि क्षत्रियों में शौर्य, वीरता, तेज एवं त्याग होना चाहिए, तभी क्षत्रिय वंश जीवित रह सकता है

"ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठरः ।

ब्राह्मणा वां शतं श्रेष्ठ मुखा देवा सृजत प्रभु ।।

बाहुभ्यां क्षत्रिय शत वैश्यानामुरुतः शतम् ।

पदभ्यां शूद्रं शतं चैव केशवो भरतर्षभ ।। " (2)

हिन्दू समाज विभिन्न जातियों और उपजातियों में बंटा हुआ था। मुगल- काल में हिन्दुओं को राज्य के बड़े पदों पर नियुक्त किया जाने लगा था। अकबर के शासनकाल में कई हिन्दुओं को उच्च मनसबदार के पद पर नियुक्त किया गया था। समाज में ब्राह्मणों का सर्वाधिक सम्मान था। दसवीं सदी के अरब लेखक अलमसूदी ने उल्लेख किया है कि हिन्दुस्तानियों में ब्राह्मण ही सर्वाधिक योग्य थे। परवर्ती लेखक अलदूदरीसी ने भी ब्राह्मणों को हिन्दू जाति में सर्वोपरि माना है। ब्राह्मण जाति के लोग व्यापार एवं कृषि कार्य भी करने लगे थे। राजपूतों को सैनिक के रूप में ख्याति प्राप्त थी। पूर्व मध्ययुगीन लेखक इब्नखुदजवा के अनुसार 'क्षत्रियों के सम्मुख सब लोग सिर झुकाते थे, लेकिन ये किसी को सिर नहीं झुकाते।' अलबरूनी के अनुसार 'क्षत्रिय वेद पढ़ता था, पढ़ाता नहीं। वह यज्ञ करता था और पुराणों के अनुरूप आचरण करता था। वह प्रजा पर शासन करता और उसकी रक्षा करता था । (3)

मुगल शासक गुणों के आधार पर ब्राह्मण, राजपूतों और कायस्थों को राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते थे और ज्योतिषियों, कवियों और विद्वानों को उनकी योग्यतानुसार दरबार में सम्मान प्राप्त था। कार्य के आधार पर हिन्दू समाज में कई नवीन उपजातियों का उदय हुआ। (4)

पार्श्वनाथ चरित में तंवरकाल में चार वर्णों के व्यक्तियों-ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय जाति व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित थी। तुलसीदास का आविर्भाव 16 वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने रामचरित मानस की रचना संवत् 1631 (1574 ई.) में आरंभ की थी। महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया था। प्रभावशाली और धनी समूहों को जातीय सोपान में उच्चतम स्थान मिलता था। जबकि आबादी के निम्नतम सामाजिक आर्थिक समूहों को निम्न जातियों में स्थान मिला। हिन्दुओं में कुछ व्यवसाय - कुछ कुलों, श्रेणियों एवं जातियों तक सीमित हो गये, कुछ जातियां ही व्यवस्था के आधार पर बन गईं थीं। (5) 'धण्णकुमार चरिउ' में इधू पटवारी जाति का उल्लेख किया है। यह वैश्य जाति के अन्तर्गत होते थे। उनका कार्य भूमि का लेखा-जोखा रखना था। सूत्रों के अतिरिक्त प्रायः सभी वर्ण और जाति के लोग इस क्षेत्र में कार्य करते थे। शूद्रों के इस क्षेत्र में कार्य न करने का कारण उनमें शिक्षा का अभाव होना था। पटवारी के कार्य के लिये शिक्षित होना अनिवार्य था। पटवारी का कार्य ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य आदि सभी जाति के लोग करते थे, इनके अतिरिक्त मुस्लिम धर्मानुयायी भी पटवारी का कार्य करते थे। अग्रवाल एवं जायसवाल नामक एक अन्य जातियों के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, जो वैश्य वर्ग की ही शाखायें थीं। कायस्थ जाति (वर्ग) का उल्लेख हिन्दू समाज के चारों वर्णों में नहीं मिलता है। इस जाति का विकास अलग वर्ग और जाति के रूप में हुआ। पद्मपुराण के उल्लेख के अनुसार कायस्थ की उत्पत्ति ब्रह्मा की काया से हुई है। श्री हर्ष ने कायस्थ की उत्पत्ति यम के लिपिक चित्रगुप्त से मानी है। (6) कायस्थों का मुख्य व्यवसाय लेखन कार्य था। तंवरकालीन 'कायस्थ वर्ग के व्यक्तियों का उल्लेख प्राप्त होता है। कायस्थ वर्ग का उल्लेख नवीं सदी से 'कायस्थ जाति' के रूप में होने लगा। समाज में 108 पेशेवर जातियों का विवरण मिलता है। ये पेशेवर जातियां विभिन्न प्रकार के पेशे अथवा व्यवसाय से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

मध्यकालीन समाज में शूद्र वर्ण की स्थिति अत्यन्त हीन एवं दयनीय थी। इस वर्ण के व्यक्तियों को विद्याध्ययन, व्यापार और सैनिक बनने का अधिकार नहीं था। शूद्रों का मुख्य कर्तव्य था उच्च वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य) की सेवा करना। शूद्रों के दो वर्ग थे पान्या एवं अपान्या। (7) पान्या अनिरखसित शूद्रों के उस वर्ग को कहते थे, जिसे उच्च वर्ण के व्यक्ति स्पर्श कर सकते थे और अपान्या निरवसित शूद्रों का वह वर्ग था, जिसे अस्पृश्य माना जाता था। हिन्दू समाज में जाति प्रथा का स्वरूप और भी अधिक जटिल हो गया था। अस्पृश्य के स्पर्श मात्र से अपवित्र होने का विचार व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान कर देता था। (8)

मोहना ग्राम में तंवर जागीरदारों के काल में चारों वर्ण के लोग ब्राह्मण,क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद थे। इनके अतिरिक्त मुगलकाल से स्थापित यहां की जागीर में मुसलमान भी निवास करते थे। ये सभी तत्कालीन समय में अपनी- अपनी सामाजिक परम्पराओं का निर्वाह करते हुए राजकीय कार्यों में भी सहयोग प्रदान कर रहे थे। विशेष अवसरों पर जागीरदार राव साहब दरबार लगाते थे। दरबार में विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक उत्सवों में गांव के जनसमूह में पुरुष, स्त्रियां और बच्चे भी भाग लेते थे। दरबार में राव साहब के द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति उनके दोनों ओर खड़े होकर चंवर ढुलाते थे। गढ़ी में लगभग 55 फीट चौड़ा दरबार हल है। विशेष उत्सवों पर यहां गांव के सभी लोग एकत्रित होते थे।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मोहना के तोमर शिव एवं शक्ति के उपासक हैं। राजपूतों की गढ़ी में शिवलय बना हुआ है, जिसमें शिव और पार्वती विराजमान हैं। दोनों ही सृष्टि के सृजनकर्ता हैं शिव का सम्बंध शक्ति से है और शक्ति का सम्बंध शिव से है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।

मुगलकाल में मोहना ग्राम स्थापित हुआ था तभी से यहां पर हिन्दू, जैन एवं मुस्लिम धर्मावलम्बी जन समूह निवास कर रहा है। गांव में जागीरदार कालीन हिन्दू, जैन मंदिर एवं मस्जिद स्थापित हैं। यहां पर हिन्दू देवी देवताओं के मंदिरों में श्यामल माता का मंदिर, गणेश की प्रतिमा, हनुमान मंदिर, गढ़ी के मुख्य भवन के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग एवं नंदी की मूर्ति, श्यामल माता के मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे राधा कृष्ण, विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा एवं अनेक शिवलिंग स्थापित हैं। गांव में जैन मंदिर एवं मस्जिद भी है। ये भी जागीरदार कालीन ही हैं। यहां के ग्रामवासी अपने-अपने धर्मानुसार धार्मिक कृत्यों के लिए स्वतंत्रत थे। जागीरदार कालीन प्रमुख पूजागृह इस प्रकार से थ।

मंदिर हमेशा आस्था एवं पूजा के प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक मंदिर का विशेष महत्त्व है। मंदिरों का सम्बन्ध विभिन्न धर्म के लोगो से है, जो अलग-अलग काल खण्डों में विभिन्न शासकों ने बनवाये । श्यामला माता शक्ति की प्रतीक हैं। इनका सम्बंध तोमर राजपूतों की कुलदेवी से है। हमारे देश में अलग-अलग राजपूतों की अलग-अलग कुलदेवी है। जैसे जादौन राजपूतों की करौली देवी, मुरैना के तोमर राजपूतों की चिल्लादेवी, राजावतों की जमुआदेवी जो जयपुर के पास स्थित है। जैसलमेर के भाटी राजपूतों की करणीदेवी एवं सिकरवार (बढ़गूजर) की कुलदेवी सती माता हैं। गढ़ी के उत्तरी भाग में मुख्य भवन के बगल में श्यामल मता का मंदिर स्थापित है। श्यामल माता गढ़ी में निवास करने वाले मोहना के तोमर जागीरदारों की कुलदेवी हैं।

पूर्व में इस मंदिर का खिड़की जैसा छोटा सा दरवाजा था। संभवतया मध्यकाल में होने वाले आक्रमणों से सुरक्षा हेतु श्यामल माता का मंदिर छोटा बनवाया होगा, ताकि माता की मूर्ति आक्रमणकारियों के हाथों में ना पड़े और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। मंदिर में श्यामल-माता की मूर्ति के ठीक बगल में विघ्नविनाशक श्रीगणेश की प्रतिमा भी स्थापित है। ये दोनों प्रतिमाएं मध्यकालीन हैं। सन् 1973 ई. में गढ़ी से प्राप्त सामग्री से ठाकुर नरेन्द्र सिंह काकाजी ने मंदिर का पुर्ननिर्माण करवाया है। वर्तमान समय में इस मंदिर में जागीरदार के परिवारजनों के अतिरिक्त गांव के निवासी भी इस मंदिर में नवदुर्गा आदि धार्मिक अवसर पर पूजन हेतु आते हैं। गढ़ी में ही श्यामल माता के मंदिर के ठीक सामने हनुमानजी की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा छोटे से मंदिर में स्थापित है। प्रतिमा जागीरदार कालीन है। इस मंदिर में भी वर्तमान समय में यहां के निवासी पूजा करते हैं।

आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग त्रिदेव को मानते हैं ब्रम्हा विष्णु एवं महेश ब्रम्हा सृष्टि के उत्पादनकर्ता, विष्णु पालनकर्ता एवं महेश सृष्टि के संघहारक हैं। श्यामल माता के मंदिर के चबूतरे से लगा हुआ पीपल का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा रखी है । इस प्रतिमा के आस-पास अनेक शिवलिंग रखे हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग खण्डित भी हैं। मुगलकालीन बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में मंदिरों के विनाश का आदेश दिया था। मासिर-ए-आलमगीरी में स्पष्ट लिखा है कि 'उसने सब प्रान्तों के गर्वनरों को काफिरो के मंदिरों, स्कूलों एवं धार्मिक रिवाजों को नष्ट करने की आज्ञा प्रदान की। (9) इस आज्ञा के परिणामस्वरूप मंदिरों का विनाश एवं मूर्तियों को तोड़ा गया था। मोहना ग्राम के मुगलकालीन निर्मित सती स्मारक की कुछ मूर्तियां एवं शिवलिंग टूटे हुए हैं। इनके टूटने

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

या खण्डित किये जाने में औरंगजेब की धर्मान्धता का आभास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई इन विष्णु-लक्ष्मी की प्रतिमा एवं शिवलिंग की पूजा वर्तमान समय में भी की जाती है।

संदर्भ सूची

1. ऋगवेद 10-15-8
2. मंडावा देवी सिंह " राजपूत शाखाओं का इतिहास" राजस्थानी साहित्य संस्थान जोधपुर संस्करण 2007 पृ.13
3. ग्यारहवीं सदी का भारत, पृ. क्र. 113 एवं मित्र, जयशंकर - प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. क्र. 18
4. खुराना के. एल. भारत का सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास, पृ. क्र.35
5. द्विवेदी, हरिहर निवास कीर्ति स्तंभ पृ. क्र. 165 व 166
6. मिश्र, जयशंकर प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, पृ. क्र. 182
7. उपाध्याय, भगवतशरण भारतीय संस्कृति के स्त्रोत, पृ. क्र. 70
8. खुराना, के. एल. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पृ.क्र. 42
9. खुराना के. एल. मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ. क्र. 91